NEXT IAS

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सिविल सेवा परीक्षा 2025

MADE EASY PUBLICATIONS
द्वारा प्रकाशित

MADE EASY Publications Pvt. Ltd.

कॉर्पोरेट कार्यालय: 44-A/4, कालू सराय
(हौज़ ख़ास मेट्रो स्टेशन के निकट), नई दिल्ली-110016
संपर्क सूत्र: 011-45124660, 8860378007
ई-मेल करें: infomep@madeeasy.in
विजिट करें: www.madeeasypublications.org

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

© कॉपीराइट: Made Easy Publications Pvt. Ltd.

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रतिलिपिकरण, पुनर्मुद्रण, प्रस्तुतीकरण और किसी ऐसे यंत्र में संग्रहण नहीं किया जा सकता, जिससे इसकी पुनर्प्राप्ति की जा सकती हो अथवा इसका स्थानांतरण, किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार) से उपर्युक्त उल्लिखित प्रकाशक की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

प्रथम संस्करण: 2024

विषयसूची

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

इकाई –I: भारत एवं उसके पड़ोसी देश

अध्याय 1

भारत की विदेश नीति : सिंहावलोकन (India's Foreign Policy: An Overview).....2

1.1 परिचय (Introduction) 2

1.2 भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत (Objectives and Principles of India's Foreign Policy) 2

1.3 भारत की विदेश नीति का विकास (Evolution of India's Foreign Policy) 3

जवाहरलाल नेहरू के अधीन विदेश नीति (Foreign Policy under Jawaharlal Nehru) 3

लाल बहादुर शास्त्री के अधीन विदेश नीति (Foreign Policy under Lal Bahadur Shastri).....6

इंदिरा गाँधी के अधीन विदेश नीति (Foreign Policy under Indira Gandhi) 7

राजीव गाँधी का कार्यकाल (Rajiv Gandhi Years) 9

नरसिम्हा राव का कार्यकाल (Narsimha Rao Period) ..10

आई.के. गुजराल का कार्यकाल (I.K. Gujral Period) 12

अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल (A. B. Vajpayee Period) 12

मनमोहन सिंह का कार्यकाल (Manmohan Singh Period).....14

नरेंद्र मोदी के अंतर्गत विदेश नीति (Foreign Policy under Narendra Modi) 16

मोदी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएँ (Key Features of the Modi Doctrine).....16

1.4 भारत की विभिन्न कूटनीतिक विशेषताएँ (India's Different Diplomatic Attributes).....18

सांस्कृतिक कूटनीति (Cultural Diplomacy) 18

खेल कूटनीति (Sports Diplomacy).....19

अंतरिक्ष कूटनीति (Space Diplomacy).....20

आर्थिक कूटनीति (Economic Diplomacy).....20

रक्षा कूटनीति (Defence Diplomacy) 21

1.5 भारतीय विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ (Challenges to Indian Foreign Policy) 23

मुख्य शब्दावली (Keywords).....23

अध्याय 2

भारत और पड़ोसी देश (India and Neighbours).....26

2.1 परिचय (Introduction) 26

2.2 दक्षिण एशिया का महत्त्व (Significance of South Asia) 26

2.3 भारत के लिए दक्षिण एशिया का महत्त्व (Significance of South Asia to India) 26

2.4 अच्छी पड़ोस नीति अपनाने के कारण (Reasons to have a Good Neighbourhood Policy)..... 27

2.5 भारत के समक्ष अपने पड़ोसियों के संबंध में विद्यमान चुनौतियाँ (Challenges before India, with Respect to its Neighbours) 27

2.6 स्वतंत्रता के बाद से अपने पड़ोसियों के प्रति भारत की नीति (India's Policy Towards its Neighbours Since Independence) 27

2.7 पड़ोस प्रथम नीति (Neighbourhood First Policy).....29

2.8 पड़ोस प्रथम नीति की चुनौतियाँ (Challenges to Neighbourhood First policy).....29

2.9 पड़ोसी प्रथम नीति में भारत के सीमावर्ती राज्यों की भूमिका (Role of Border States of India, in the Neighbourhood First Policy).....30

2.10 अपनी पड़ोस नीति को मज़बूत करने के लिए भारत की पहल (Initiatives of India to Strengthen its Neighbourhood Policy).....30

सार्क (SAARC) 30

बिम्सटेक (BIMSTEC) 30

2.11 निष्कर्ष (Conclusion) 31

अध्याय 3

भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh) 32

3.1 परिचय (Introduction) 32

3.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 32

3.3 भारत के लिए बांग्लादेश का महत्त्व (Significance of Bangladesh to India) 33

सुरक्षा (Security) 33

उत्तर-पूर्व भारत तक संपर्क (Connectivity to North East India) 33

ऐक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy)....33
हिंद महासागर में अपने प्रभाव क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण (Consolidating Sphere of Influence in the Indian Ocean)....33
3.4 बांग्लादेश के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Bangladesh)....34
3.5 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation)....34
राजनीतिक (Political)....34
रक्षा (Defence)....34
सुरक्षा और सीमा प्रबंधन (Security and Border Management)....35
आर्थिक संबंध (Economic)....35
नदी जल का बँटवारा (Sharing of River Water)....36
लोगों के मध्य संपर्क (People to People Contacts)....36
ऊर्जा (Energy)....37
संपर्क (Connectivity)....37
तकनीकी सहयोग (Technical Cooperation)....38
जलवायु (Climate)....38
कोविड के दौरान सहयोग (Covid Cooperation)....39
3.6 प्रमुख मुद्दे (Major Issues)....39
चीन का प्रभाव (China's Influence)....39
अवैध प्रवासन और उग्रवाद का मुद्दा (Illegal Migration and Insurgency Issue)....39
तीस्ता जल मुद्दा (Teesta Water Issue)....39
रोहिंग्या संकट (Rohingya Crisis)....39
सीमा विवाद (Border Disputes)....39
मवेशियों की तस्करी (Cattle Smuggling)....40
नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act CAA)....40
सांप्रदायिक मुद्दे (Communal Issues)....40
3.7 प्रमुख पहल (Major Initiatives)....40
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (Space Technology)....40
सांस्कृतिक (Cultural)....40
भूमि सीमा समझौता (Land Boundary Agreement)....41
3.8 भारत-बांग्लादेश संबंधों में हालिया घटनाक्रम (Recent Developments in India-Bangladesh Ties)....42
नवीनतम घटनाक्रम (Latest Developments)....42
BBIN मोटर वाहन समझौता (MVA)....43
3.9 निष्कर्ष (Conclusion)....44
मुख्य बिंदु (Keywords)....44

अध्याय 4

भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan)....45
4.1 परिचय (Introduction)....45
4.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)....45
4.3 द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत की पहल (India's Initiatives to Improve Bilateral Ties)....46
ताशकंद समझौता (Tashkent Agreement)....46
शिमला समझौता (Shimla Agreement)....47
4.4 कश्मीर: एक अनुचित पाकिस्तानी सनक (Kashmir: An illegitimate Pakistani Obsession)....47
4.5 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation)....49
राजनीतिक (Political)....49
व्यावसायिक (Commercial)....49
दोनों देशों के लोगों के मध्य संपर्क (People to People Contacts)....49
सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty)....50
संपर्क (Connectivity)....50
4.6 प्रमुख मुद्दे (Major Issues)....50
कश्मीर (Kashmir)....50
सीमा पार आतंकवाद (Cross Border Terrorism)....50
सीमा विवाद (Border Disputes)....51
पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन (Ceasefire Violation by Pakistan)....52
अन्य मामले (Other Issues)....52
अनुच्छेद 370 का उन्मूलन और पाकिस्तान संबंध (Article 370 Abrogation & Pakistan Link)....52
4.7 भावी उपाय (Future Measures)....52
प्रमुख शब्दावली (Keywords)....54

अध्याय 5

भारत-श्रीलंका (India-Sri Lanka)....55
5.1 परिचय (Introduction)....55
5.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)....55
5.3 भारत के लिए श्रीलंका का महत्त्व (Significance of Sri Lanka to India)....56
पड़ोसी प्रथम नीति (Neighbourhood First Policy)....56

सांस्कृतिक संबंध (Cultural Ties) 56
हिंद महासागर में प्रभाव क्षेत्र (Sphere of Influence in Indian Ocean) 57
बहुपक्षीय समूह (Multilateral Groupings) 57
5.4 श्रीलंका के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Sri Lanka) 57
सशक्त सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider) 57
वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता (Supplier of Goods) 57
भारत द्वारा अनुदान (Providing Grants) 57
5.5 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation) 58
राजनीतिक सहयोग (Political Coopeartion) 58
तमिल नागरिकता सहयोग (Tamil Citizenship Cooperation) 58
गृहयुद्ध (Civil War) 58
आर्थिक सहयोग (Economic Cooperation) 59
विकासात्मक सहयोग (Developmental Cooperation) 59
पर्यटन (Tourism) 59
मानव संसाधन विकास (Human Resource Development) 59
जलवायु सहयोग (Climate Cooperation) 59
5.6 चिंता का क्षेत्र (Areas of Concern) 60
चीन का प्रभाव (Chinese Influence) 60
पाकिस्तान फैक्टर (Pakistan Factor) 60
तमिल राष्ट्रवाद (Tamil Nationalism) 60
हिंद महासागर में मत्स्यन का अधिकार (Fishing Rights Over Indian Ocean) 60
कच्चातीवु द्वीप मुद्दा (Katchatheevu Island Issue) ...61
राजनीतिक उथल-पुथल (Political Turmoil) 61
2022 के आर्थिक संकट में श्रीलंका की मदद करने में भारत की भूमिका (Role of India in Helping Sri Lanka in The 2022 Economic Crisis) 62
भारत के लिए श्रीलंका से सबक (Sri Lankan Lessons For India) 62
5.7 प्रमुख पहल (Major Initiatives) 62
हाल ही की पहलें (Recent Initiatives) 63
5.8 निष्कर्ष (Conclusion) 63
कीवर्ड (Keywords) 63

अध्याय 6

भारत-अफ़ग़ानिस्तान (India-Afghanistan) **64**
6.1 परिचय (Introduction) 64
6.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 64
6.3 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation) 64
राजनीतिक (Political) 64
व्यापार एवं वाणिज्य (Trade and Commerce) 65
सांस्कृतिक संबंध (Cultural Relations) 65
विकास संबंधी सहायता (Developmental Aid) 66
हालिया घटनाक्रम (Recent Developments) 67
6.4 भारत के लिए अफ़ग़ानिस्तान का महत्त्व (Significance of Afghanistan to India) 67
6.5 संयुक्त राज्य अमेरिका और अफ़ग़ानिस्तान (USA and Afghanistan) 67
6.6 अफ़ग़ानिस्तान में भारत के लिए चुनौतियाँ (Challenges for India in Afghanistan) .68
6.7 तालिबान के कब्ज़े के पश्चात् भारत-अफ़ग़ान संबंध (India-Afghan Relations after Taliban Takeover) .69
तालिबान शासन (Taliban Regime) 69
तालिबान का वर्तमान परिदृश्य (Present Scenario of Taliban) 69
वर्तमान परिस्थिति में भारत का रुख (India's Stand in the Current Situation) 70
6.8 तालिबान और अफ़ग़ानिस्तान के प्रति भारत का नया दृष्टिकोण (India's Recalibrated Approach to Taliban and Afghanistan) 70
6.9 निष्कर्ष (Conclusion) 71
प्रमुख शब्दावली (Keywords) 71

अध्याय 7

भारत-चीन (India-China) 72
7.1 परिचय (Introduction) 72
7.2 भारत के लिए चीन का महत्त्व (Significance of China to India) 72
आर्थिक (Economic) 72
चीन-प्रेरित बढ़ावा (China Induced Boost) 72
पाकिस्तान संकट (Pakistan Trouble) 72
भारत को निर्यात (Exports to India) 72
7.3 चीन के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to China) 73
आर्थिक (Economic) 73
भू-राजनीतिक (Geopolitical) 73

सुरक्षा (Security) 73
चीन की वैश्विक नेता बनने की महत्वाकांक्षा (China's Ambition of Global Leader) 73
7.4 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation) 73
राजनीतिक (Political) 73
व्यापार (Trade) 75
सांस्कृतिक (Cultural) 75
प्रवासी (Diaspora) 75
रक्षा (Defence) 76
सुरक्षा (Security) 76
7.5 द्यबहुपक्षीय सहयोग (Multilateral Cooperation) 76
ब्रिक्स (BRICS) 76
शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organization, SCO) 76
रूस-भारत-चीन त्रिपक्षीय (Russia-India-China Trilateral: RIC) 77
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) 77
विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization, WTO) 77
बेसिक (BASIC) 77
जी-77 (G-77) 77
जी-33 (G-33) 77
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) 77
जी-20 (G-20) 77
जलवायु परिवर्तन (Climate Change) 78
7.6 क्षेत्र और विश्व से संबंध का महत्त्व (Significance of Relationship to Region and World) 78
7.7 संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in Relations) 78
सीमा विवाद (Border Disputes) 78
डोकलाम गतिरोध (Doklam Standoff) 79
लद्दाख/गलवान संघर्ष (Ladakh/Galwan Conflict) 80
विवादास्पद मानचित्र विवाद (Controversial Map Dispute) 81
मोतियों की माला (String of Pearls) 82
जल विवाद (Water Dispute) 82
दलाई लामा और तिब्बत (Dalai Lama and Tibet) 82
अरुणाचल प्रदेश और वीज़ा का मुद्दा (Arunachal Pradesh and Visa Issue) 82
भूटान और नेपाल (Bhutan and Nepal) 82
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative - BRI) 83
म्यांमार संकट पर (On Myanmar Crisis) 84
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में (In United Nation Security Council) 84
भारत-अमेरिका और उसके सहयोगियों की निकटता (India-USA and its Allies Closeness) 84
हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) 84
आर्थिक (Economic) 85
अंतर्राष्ट्रीय मंच (International Fora) 86
दक्षिण चीन सागर (South China Sea) 86
7.8 चीन-भारत प्रतिस्पर्धा (Sino-India Competition) 87
7.9 आगे की राह (Way Forward) 88
7.10 निष्कर्ष (Conclusion) 89
प्रमुख शब्द (Keywords) 89

अध्याय 8

भारत-भूटान (India-Bhutan) 91
8.1 भूमिका (Introduction) 91
8.2 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation) 91
राजनीतिक (Political) 91
आर्थिक (Economic) 91
जल विद्युत सहयोग (Hydro Power Cooperation) 91
सांस्कृतिक (Cultural) 92
रक्षा (Defense) 92
8.3 भारत के लिए भूटान का महत्त्व (Significance of Bhutan to India) 92
रणनीतिक अवस्थिति (Strategic Location) 92
ऊर्जा (Energy) 92
क्षेत्रीय सहयोग (Regional Cooperation) 92
चीनी कारक (Chinese Factor) 93
8.4 भूटान के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Bhutan) 93
8.5 क्षेत्र को व्यापक लाभ (Overall Benefits to the Region) 93
8.6 संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in Relations) 93
हालिया घटनाक्रम (Recent Development) 94
8.7 निष्कर्ष (Conclusion) 94
प्रमुख शब्द (Keywords) 94

अध्याय 9

भारत-नेपाल (India-Nepal) 95
9.1 परिचय (Introduction) 95
9.2 भारत के लिए नेपाल का महत्त्व (Significance of Nepal to India) 97
9.3 नेपाल के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Nepal) 97
9.4 सहयोग का क्षेत्र (Area of Cooperation) 97
राजनीतिक (Political) 97
आर्थिक (Economic) 98
रक्षा (Defence) 99
सांस्कृतिक (Cultural) 99
जल संसाधन सहयोग (Water Resource Cooperation) 99
ऊर्जा सहयोग (Energy Cooperation) 99
आधारभूत संरचना (Infrastructure) 99
ट्रांस-हिमालयी बहुआयामी संपर्क नेटवर्क (Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network) 99
नेपाल को भारत की विकास सहायता (India's Development Assistance to Nepal) 99
पश्चिम सेती विद्युत परियोजना (West Seti Power Project) 99
9.5 संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in Relationship) 99
जल विवाद (Water Dispute) 99
सीमा विवाद (Border Issues) 100
सुरक्षा (Security) 100
चीन की संलिप्तता (Involvement of China) 100
मधेसी मुद्दा (Madhesis Issue) 100
विलंबित परियोजनाएँ (Delayed Projects) 100
हालिया विकास (Recent Development) 100
9.6 संबंधों का भविष्य (Future of Relations) 100
9.7 निष्कर्ष (Conclusion) 101
प्रमुख शब्द (Keywords) 101

अध्याय 10

भारत-म्यांमार (India-Myanmar) 102
10.1 परिचय (Introduction) 102
10.2 भारत के लिए म्यांमार का महत्त्व (Significance of Myanmar for India) 102
10.3 म्यांमार के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India for Myanmar) 103
10.4 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation) 103
राजनीतिक (Political) 103
सांस्कृतिक (Cultural) 104
आर्थिक (Economic) 104
व्यापार और पारगमन (Trade and Transit) 104
प्रवासी (Diaspora) 105
क्षेत्रीय सहयोग (Regional Cooperation) 105
10.5 संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in Relations) 106
पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह (Insurgency in North East India) 106
आर्थिक (Economic) 106
संपर्क (Connectivity) 106
चीन के साथ संबंध (Relations with China) 106
सीमा-पार उग्रवाद (Trans-Border Militancy) 106
रोहिंग्या संकट (Rohingya Crisis) 106
म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability in Myanmar) 107
10.6 आगे की राह (Way Forward) 107
10.7 निष्कर्ष (Conclusion) 107
प्रमुख शब्द (Keywords) 107

अध्याय 11

भारत-मालदीव (India-Maldives) 108
11.1 परिचय (Introduction) 108
11.2 भारत के लिए मालदीव का महत्त्व (Significance of Maldives to India) 108
11.3 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation) 108
राजनीतिक (Political) 108
आर्थिक (Economic) 109
विकास सहायता (Development Assistance) 109
रक्षा (Defence) 109
प्रवासी और संस्कृति (Diaspora and Culture) 110
क्षेत्रीय सहयोग (Regional Cooperation) 110

11.4 संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in Relations).....110
राजनीतिक अस्थिरता (Political Instability).....110
चीन के साथ संबंध (Relation with China).....110
कट्टरवाद और आतंकवाद (Radicalisation and Terrorism).....111
हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region - IOR)..111
जलवायु परिवर्तन (Climate Change).....111
विकास (Development).....111
GMR मुद्दे (GMR Issue).....111
भारत विरोधी भावना (Anti India Sentiment).....111
11.5 आगे की राह (Way Forward).....112
11.6 निष्कर्ष (Conclusion).....112

अध्याय 12

भारत-मॉरीशस (India-Mauritius).....113
12.1 व्यापारिक संबंध (Trade Relations).....113
12.2 सैन्य संबंध (Military Relations).....113
12.3 सांस्कृतिक संबंध (Cultural Relations).....113
12.4 भारत-मॉरीशस स्वास्थ्य सहयोग (India-Mauritius Health Cooperation).....114
12.5 भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग तथा भागीदारी समझौते (India-Mauritius Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement: CECPA).....114
12.6 हालिया विकास (Recent Developments).....114

इकाई –II: भारत एवं उसका विस्तारित पड़ोस

अध्याय 13

भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया (India and Southeast Asia).....116
13.1 परिचय (Introduction).....116
13.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background).....116
13.3 स्वतंत्रता के बाद से दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रति भारत का दृष्टिकोण (India's Approach Towards South East Asia Since Independence).....117
13.4 पूर्व की ओर देखो नीति से पूर्व में काम करो की नीति (Look East Policy to Act East Policy).....117
पूर्व की ओर देखो नीति (Look East Policy).....117
एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy).....118
13.5 दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन (Association of South East Asian Nations: ASEAN).....119
पृष्ठभूमि (Background).....119
आसियान के स्तंभ (Pillars of ASEAN).....120
आसियान-भारत संबंध (ASEAN-India Relations).....120
13.6 आसियान-भारत संबंधों का महत्त्व (Significance of ASEAN-India Relations).....120
13.7 भारत के लिए आसियान का महत्त्व (Significance of ASEAN to India).....121
13.8 आसियान के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to ASEAN).....122
13.9 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....122
राजनीतिक (Political).....122
आर्थिक (Economic).....122
लोगों से लोगों के बीच संपर्क (People to People Contact).....122
सांस्कृतिक (Cultural).....123
सुरक्षा (Security).....123
संपर्क (Connectivity).....123
कृषि (Agriculture).....123
विकासात्मक सहायता (Developmental Assistance).....124
हालिया शिखर सम्मेलन (Recent Summit).....124
13.10 आसियान-भारत संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in ASEAN – India Relations).....124
13.11 संबंधों का भविष्य (Future of Relations).....125
13.12 अन्य उप-क्षेत्रीय संगठन (Other Sub-Regional Organizations).....125
मेकांग-गंगा सहयोग (MGC).....125
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit).....126
हालिया शिखर सम्मेलन (Recent Summit).....127
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP).....127
13.13 अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय संबंध (Bilateral Relations with other Southeast Asian Nations).....128
भारत-सिंगापुर (India-Singapore).....128
भारत-इंडोनेशिया (India-Indonesia).....130
भारत-वियतनाम (India-Vietnam).....131
भारत-मलेशिया (India-Malaysia).....133
भारत-थाईलैंड (India-Thailand).....134

संपर्क (Connectivity) 134
मुख्य बिंदु (Keywords) 134

अध्याय 14

भारत और पश्चिम एशिया (India and West Asia) 135
14.1 परिचय (Introduction) 135
14.2 भारत की पश्चिम एशिया नीति का विकास (Evolution of India's West Asia Policy) ... 136
14.3 पश्चिम एशियाई क्षेत्र का महत्त्व (Significance of West Asian Region) 136
14.4 पश्चिम एशिया नीति के प्रति भारत का दृष्टिकोण (India's Approach towards West Asia Policy) 137
पश्चिम की ओर देखो नीति (Look West Policy) 137
पाकिस्तान कारक (Pakistan Factor) 137
14.5 खाड़ी क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताएँ (India's Priorities in the Gulf) 137
14.6 पश्चिम एशियाई नीति में चुनौतियाँ (Challenges in West Asian Policy) 138
14.7 आगे की राह (Way Forward) 138
प्रमुख शब्द (Keywords) 138

अध्याय 15

भारत-सऊदी अरब (India-Saudi Arabia) 139
15.1 परिचय (Introduction) 139
15.2 भारत के लिए सऊदी अरब का महत्त्व (Significance of Saudi Arabia to India) 139
15.3 सऊदी अरब के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Saudi Arabia) 140
15.4 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation) 140
राजनीतिक (Political) 140
आर्थिक (Economic) 140
रक्षा सहयोग (Defence Cooperation) 141
ऊर्जा (Energy) 141
प्रवासी और संस्कृति (Diaspora and Culture) 141
पारस्परिक लाभ (Mutual Benefits) 142
सहयोग के अन्य क्षेत्र (Other Areas of Cooperation) 142
15.5 संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in Relations) 142
हालिया विकास (Recent Development) 143
15.6 आगे की राह (Way Forward) 143
15.7 निष्कर्ष (Conclusion) 144

अध्याय 16

भारत-ईरान (India-Iran) 145
16.1 परिचय (Introduction) 145
16.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 145
1979 ईरानी क्रांति (Iranian Revolution) 145
16.3 भारत के लिए ईरान का महत्त्व (Significance of Iran to India) 146
संपर्क (Connectivity) 146
16.4 ईरान के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Iran) 148
16.5 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation) 148
राजनीतिक (Political) 148
व्यापारिक संबंध (Trade Relations) 148
ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) 148
संपर्क (Connectivity) 149
सांस्कृतिक संबंध एवं प्रवासी (Cultural Relations and Diaspora) 149
मानवीय सहायता (Humanitarian Assistance) 149
16.6 संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in Relations) 149
16.7 महत्त्वपूर्ण विकास: एक विश्लेषण (Critical Developments: An Analysis) 151
ईरान-पाकिस्तान संबंधों की वर्तमान स्थिति 151
16.8 हालिया घटनाक्रम (Recent Developments) 152
इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए (Ebrahim Raisi Elected as New President of Iran) 152
ईरान-अमेरिका परमाणु समझौते का पुनरुद्धार (Revival of Iran-USA Nuclear Deal) 152
16.9 भारत-ईरान संबंधों का भविष्य: एक दृष्टिकोण (Future of India-Iran Relations: A Perspective) 152
16.10 निष्कर्ष (Conclusion) 153
प्रमुख बिंदु (Keywords) 153

अध्याय 17

भारत-इज़राइल (India-Israel) 154
17.1 परिचय (Introduction) 154
17.2 इज़राइल का भारत के लिए महत्त्व (Significance of Israel to India) 154

17.3 इज़राइल के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Israel).....155
17.4 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....155
राजनीतिक (Political).....155
आर्थिक और वाणिज्यिक (Economic and Commercial).....156
निवेश (Investment).....156
कृषि (Agriculture).....156
रक्षा और सुरक्षा (Defence and Security).....156
रक्षा उपकरण (Defence Equipment).....156
साइबर सुरक्षा (Cyber Security).....157
आतंकवाद (Terrorism).....157
विज्ञान और तकनीक (Science and Technology).....157
अंतरिक्ष सहयोग (Space Cooperation).....157
संस्कृति और प्रवासी (Culture and Diaspora).....157
17.5 संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in Relations).....157
डी-हाइफनेशन (DE-HYPHENATION).....159
17.6 भारत-इज़राइल संबंध: आलोचनात्मक दृष्टिकोण (India-Israel Relations: Critical Perspectives)...159
17.7 नवीनतम घटनाक्रम (Recent Developments).....160
पश्चिम एशिया शांति योजना (West Asia Peace Plan).....160
नया क्वाड/चतुष्पक्षीय आर्थिक मंच (New Quad/Quadrilateral Economic Forum).....161
17.8 निष्कर्ष (Conclusion).....162
प्रमुख शब्दावली (Keywords).....162

अध्याय 18

भारत-संयुक्त अरब अमीरात (India-UAE).....163
18.1 परिचय (Introduction).....163
18.2 संयुक्त अरब अमीरात का भारत के लिए महत्त्व (Significance of UAE to India).....163
रणनीतिक (Strategic).....163
आर्थिक (Economic).....164
प्रवासी समुदाय का हित (Diaspora's Interest).....164
18.3 संयुक्त अरब अमीरात के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to UAE).....164
18.4 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....164
राजनीतिक (Political).....164
नवीनतम प्रयास (Recent Intitative).....165
आर्थिक सहयोग (Economic Cooperation).....166
निवेश (Investment).....166
रक्षा सहयोग (Defence Cooperation):.....166
संस्कृति और प्रवासी (Culture and Diaspora).....167
आतंकवाद और सुरक्षा (Terrorism and Security).....167
18.5 संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in Relations).....168
18.6 भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) [India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)].....168
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) का महत्त्व (Significance of the CEPA).....169
18.7 भारत-संयुक्त अरब अमीरात संबंध: महत्त्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य (India-UAE Relations: Critical Perspectives).....169
18.8 आगे की राह (Way Forward).....170
18.9 निष्कर्ष (Conclusion).....170
प्रमुख शब्दावली (Keywords).....170

अध्याय 19

यमन, बहरीन एवं क़तर के साथ संबंध (Relation With Yemen, Bahrain and Qatar).....171
19.1 भारत-यमन (India-Yemen).....171
परिचय (Introduction).....171
यमन संकट एवं भारत का हित (Yemen Crisis and India's Stake).....171
यमन संकट का प्रभाव (Impact of Yemen Crisis).....172
भारत के लिए यमन का महत्त्व (Importance of Yemen to India).....172
ऑपरेशन राहत (Operation Raahat).....172
19.2 भारत-बहरीन (India-Bahrain).....173
परिचय (Introduction).....173
सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....173
बहरीन के साथ महत्त्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (Important MOU's Signed with Bahrain)174
भारत के लिए बहरीन का महत्त्व (Significance of Bahrain to India).....174
आगे की राह (Way Forward).....175
19.3 भारत-क़तर (India-Qatar).....175
परिचय (Introduction).....175
भारत के लिए क़तर का महत्त्व (Significance of Qatar to India).....175
सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....175

कोविड सहयोग (Covid Cooperation).....176
क़तर संकट और उसका प्रभाव (Qatar Crisis and its Impact).....177
प्रभाव (Impact).....177
आलोचनात्मक दृष्टिकोण (Critical Perspectives).....178
निष्कर्ष (Conclusion).....178

अध्याय 20

खाड़ी सहयोग परिषद् एवं इस्लामिक सहयोग संगठन (Gulf Cooperation Council and Organization of Islamic Cooperation).....179

20.1 खाड़ी सहयोग परिषद् (Gulf Cooperation Council: GCC).....179
परिचय (Introduction).....179
उद्देश्य (Objectives).....179
भारत और खाड़ी सहयोग परिषद् (India and GCC).....179
खाड़ी सहयोग परिषद् की संरचना (Structure of GCC).....179
भारत के लिए जीसीसी का महत्त्व (Significance of GCC to India).....180
सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....180
आर्थिक संबंध (Economic Relation).....180
भारत-GCC मुक्त व्यापार समझौता (India-GCC FTA).....180
आतंकवाद एवं सुरक्षा (Terrorism and Security).....180
GCC को लेकर भारत के समक्ष चुनौतियाँ (Challenges India Faces with GCC).....180
जीसीसी वार्षिक बैठक 2021 की मुख्य विशेषताएँ (Highlights of GCC Annual Meeting 2021).....181
हालिया घटनाक्रम (Recent Development).....181
निष्कर्ष (Conclusion).....181

20.2 इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization of Islamic Cooperation: OIC).....181
परिचय (Introduction).....181
ओआईसी की स्थापना क्यों की गई? (Why was the OIC Established?).....182
ओआईसी के उद्देश्य (Objectives of OIC).....182
ओआईसी का कार्य (Working of OIC).....182
ओआईसी के समक्ष समस्याएँ (Issues Faced with OIC).....182
ओआईसी और भारत (OIC and India).....182
भारत के लिए ओआईसी का महत्त्व (Significance of OIC to India).....183
ओआईसी और कश्मीर मुद्दा (OIC and Kashmir Issue).....183
आगे की राह (Way Forward).....183
निष्कर्ष (Conclusion).....183
प्रमुख शब्दावली (Keywords).....183

अध्याय 21

भारत और मध्य एशिया (India and Central Asia).....184

21.1 परिचय (Introduction).....184
21.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background).....184
मध्य एशिया - बड़े खेल के लिए नया रंगमंच (Central Asia -New Theatre for Great Game).....185
21.3 मध्य एशिया के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Central Asia).....185
21.4 भारत के लिए मध्य एशिया का महत्त्व (Significance of Central Asia to India).....185
21.5 मध्य एशिया के प्रति भारत की नीति (India's Policy towards Central Asia).....186
सहयोग का क्षेत्र (Area of Coorperation).....186
21.6 कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति (Connect Central Asia Policy).....187
21.7 मध्य एशिया में भारत और चीन (India and China in Central Asia).....189
शंघाई सहयोग संगठन (SCO).....189
चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (China's Belt and Road Initiative).....189
21.8 भारत-कज़ाखिस्तान (India-Kazakhstan).....190
सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....190
21.9 भारत-उज़्बेकिस्तान (India-Uzbekistan).....192
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background).....192
सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....192
भारत के लिए उज़्बेकिस्तान का महत्व (Significance of Uzbekistan to India).....193
उज़्बेकिस्तान के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Uzbekistan).....193
संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in Relations).....194
भविष्य की संभावनाएँ (Future Prospects).....194

21.10 भारत-तुर्कमेनिस्तान (India-Turkmenistan) 194
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 195
सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation)..... 195
संबंध में चुनौतियाँ (Challenges in the Relation) 195
भविष्य की संभावनाएं (Future Prospects) 195
21.11 भारत-किर्गिस्तान (India-Kyrgyzstan)..... 195
सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation)..... 195
भविष्य की संभावनाएं (Future Prospects) 197
21.12 भारत-ताज़िकिस्तान (India-Tajikistan) 197
सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation)..... 198
भविष्य की संभावनाएं (Future Prospects) 199
21.13 मध्य एशिया में आगे की राह (Way Forward in Central Asia)..... 200

इकाई -III: कुछ महत्त्वपूर्ण देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध

अध्याय 22

भारत-यूएसए (India and USA) 202
22.1 अवलोकन (Overview)..... 202
22.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 202
22.3 उद्भव: शीत युद्ध से वर्तमान तक (Evolution: Cold War to Present)..... 203
22.4 संबंधों में सुधार (Improvement in Relationship) 203
22.5 21वीं सदी के लिए विज़न (Vision for 21st Century)..... 204
22.6 भारत-अमेरिका संबंधों का महत्त्व (Significance of India-USA Relationship) 205
सामरिक अभिसरण (Strategic Convergence) 205
मध्य पूर्व (Middle East)..... 205
दक्षिण चीन सागर (South China Sea)..... 205
एशिया में संतुलन (Balance in Asia)..... 205
अफ़ग़ानिस्तान स्थिरता (Afghanistan Stability)..... 205
आतंकवाद (Terrorism)..... 205
रक्षा और सुरक्षा (Defence and Security)..... 205
UNSC और मिसाइल प्रौद्योगिकी व्यवस्थाएँ (UNSC and Missile Technology Regimes)..... 206
'क्वाड' की वापसी (Coming Back of 'QUAD') 206
22.7 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation)..... 206
राजनीतिक (Political)..... 206
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International Cooperation) 207
आर्थिक (Economic)..... 208
रक्षा (Defence)..... 208
असैन्य परमाणु सहयोग (Civil Nuclear Cooperation)..... 209
ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन (Energy and Climate Change)..... 210
आतंकवाद-रोधी और आंतरिक सुरक्षा (Counter-terrorism and Internal Security) 211
विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology)..211
अंतरिक्ष (Space) 212
प्रवासी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान (Diaspora and Cultural Exchanges) 212
सहयोग के अन्य क्षेत्र (Other Areas of Cooperation) 212
22.8 अमेरिका की 'एशिया धुरी' नीति पर भारत (India on USA's 'Asia Pivot' Policy) 213
22.9 हालिया घटनाक्रम (Recent Developments)..... 213
22.10 संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in Relations)..... 214
रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना (Maintaining Strategic Autonomy) 215
वीज़ा मुद्दा (Visa Issue)..... 215
व्यापार संबंधी मुद्दे (Trade Issues)..... 215
टोटलाइज़ेशन एग्रीमेंट (Totalization Agreement) 216
22.11 निष्कर्ष (Conclusion)..... 216
प्रमुख शब्द (Keywords) 217

अध्याय 23

भारत-रूस (India-Russia) 218
23.1 परिचय (Introduction) 218
23.2 भारत-USSR संबंधों की ऐतिहासिक विरासत (Historical Legacy of Indo-USSR Relations) 218
23.3 भारत के लिए रूस का महत्त्व (Significance of Russia to India)..... 220
रणनीतिक लाभ (Strategic Advantage)..... 220
रक्षा और सुरक्षा सहयोग (Defence and Security Cooperation)..... 220
व्यापार और आर्थिक सहयोग (Trade and Economic Cooperation) 220

बहुपक्षीय सहयोग (Multilateral Cooperation) 220
ऊर्जा (Energy).....220
23.4 रूस के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Russia).....221
23.5 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....221
राजनीतिक (Political).....221
आर्थिक (Economic).....221
प्रवासी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान (Diaspora and Cultural Exchanges) 222
रक्षा (Defence).....222
परमाणु (Nuclear).....223
ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा (Energy and Infrastructure) 223
विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology).....223
आतंकवाद (Terrorism).....224
साइबर सुरक्षा (Cyber Security).....224
23.6 संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges to Relations) 224
23.7 ब्रिक्स, आरआईसी और एससीओ (BRICS, RIC and SCO).....225
23.8 संबंधों को मज़बूत करना (Strengthening Links).....225
23.9 निष्कर्ष (Conclusion).....226
प्रमुख शब्द (Keywords) 226

अध्याय 24

भारत-जापान (India-Japan).....227
24.1 परिचय (Introduction) 227
24.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 227
24.3 भारत के लिए जापान का महत्त्व (Significance of Japan to India) 228
24.4 जापान के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Japan) 228
24.5 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....228
राजनीतिक (Political).....228
रक्षा (Defence).....229
आर्थिक और वाणिज्यिक (Economic and Commercial).....229
बहुपक्षीय सहयोग (Multilateral Cooperation) 230
परमाणु समझौता (Nuclear Deal).....230
विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science - Technology) 230
सांस्कृतिक (Cultural).....231
24.6 सहयोग के अन्य क्षेत्र (Other Areas of cooperation).....231
हालिया विकास (Recent Development) 231
24.7 निष्कर्ष (Conclusion).....233

अध्याय 25

भारत-दक्षिण कोरिया (India-South Korea).....234
25.1 परिचय (Introduction) 234
25.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 234
25.3 क्षेत्र के लिए महत्त्व (Significance for the Region).....235
25.4 भारत के लिए दक्षिण कोरिया का महत्त्व (Significance of South Korea to India).....235
रणनीतिक (Strategic).....235
अवसंरचना (Infrastructure) 235
25.5 दक्षिण कोरिया के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to South Korea).....235
25.6 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....235
राजनीतिक (Political).....235
आर्थिक (Economic).....236
रणनीतिक सहयोग (Strategic Cooperation).....236
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science & Technology).....236
परमाणु शक्ति (Nuclear) 237
सांस्कृतिक (Cultural).....237
25.7 निष्कर्ष (Keywords).....237
मुख्य शब्दावली (Keywords).....237

अध्याय 26

भारत-ऑस्ट्रेलिया (India-Australia).....238
26.1 परिचय (Introduction) 238
26.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 238
26.3 क्षेत्र के लिए महत्त्व (Significance for the Region).....239
समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) 239
क्षेत्रीय संरचना (Regional Architecture) 239

26.4 भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया का महत्त्व (Significance of Australia to India) 239
भारत की ऐक्ट ईस्ट नीति (India's Act East Policy) 239
बहुपक्षीय मंचों की सदस्यता (Membership to Multilateral Forums) 239
हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) 239
चीन की मुखरता (Assertiveness of China) 240
ऊर्जा (Energy)....240
26.5 ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Australia) 240
रणनीतिक (Strategic)....240
व्यापार और निवेश (Trade and Investment)....240
26.6 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation)....240
असैन्य परमाणु सहयोग (Civil Nuclear Cooperation)....243
सुरक्षा (Security) 243
सांस्कृतिक (Cultural)....243
खेल (Sports) 244
कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Agriculture, Science and Technology) 244
ऊर्जा और खनिज संसाधन (Energy and Mineral Resources) 244
26.7 संबंधों में विद्यमान चुनौतियाँ (Challenges in Relations) 244
26.8 निष्कर्ष (Conclusion)....244
मुख्य शब्दावली (Keywords)....244

अध्याय 27

भारत-यूरोपीय संघ (India-European Union)....245
27.1 परिचय (Introduction) 245
27.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 245
27.3 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation)....246
राजनीति और सुरक्षा (Political and Security) 246
व्यापार और निवेश (Trade and Investment)....246
रक्षा (Defence)....247
गतिशीलता/प्रवास (Mobility/Migration)....247
संस्कृति और शिक्षा (Culture - Education) 247
27.4 भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (India-EU Free Trade Agreement–FTA)....247
27.5 आगे की राह (Way Forward)....248
प्रमुख शब्द (Keywords) 248

अध्याय 28

भारत-फ़्रांस (India-France)....249
28.1 परिचय (Introduction) 249
28.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 249
28.3 भारत के लिए फ़्रांस का महत्त्व (Significance of France to India) 249
28.4 फ़्रांस के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to France) 250
28.5 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation)....250
राजनीतिक (Political)....250
रक्षा (Defence)....251
आर्थिक (Economic)....252
असैन्य परमाणु सहयोग (Civil Nuclear Cooperation)....252
अंतरिक्ष (Space) 252
प्रवासी और सांस्कृतिक विनिमय (Diaspora and Cultural Exchanges)....253
हालिया विकास (Recent Development) 253
28.6 संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in Relations) 253
28.7 आगे की राह (Way Forward)....253
28.8 निष्कर्ष (Conclusion)....253
प्रमुख शब्दावली (Keywords) 254

अध्याय 29

भारत-जर्मनी (India-Germany)....255
29.1 परिचय (Introduction) 255
29.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 255
29.3 भारत के लिए जर्मनी का महत्त्व (Significance of Germany to India)....255
29.4 जर्मनी के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Germany)....256
29.5 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation)....256
राजनीतिक (Political)....256
आर्थिक सहयोग (Economic Cooperation)....257
विकास सहयोग (Development Cooperation):....258

रक्षा (Defence).....258
संस्कृति और प्रवासी (Culture and Diaspora).....258
पर्यावरण सहयोग (Environmental Cooperation).....259
विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग (Science & Technology Cooperation).....259
कोविड सहयोग (Covid Cooperation).....259
29.6 भारत-जर्मनी संबंधों के लिए चुनौतियाँ (Challenges to Indo-German Relations).....259
29.7 निष्कर्ष (Conclusion).....260
प्रमुख शब्दावली (Keywords).....260

अध्याय 30

भारत-ब्रिटेन (India-UK).....261
30.1 परिचय (Introduction).....261
30.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background).....261
30.3 भारत के लिए ब्रिटेन का महत्त्व (Significance of Britain to India).....262
30.4 ब्रिटेन के लिए भारत का महत्त्व (Significance of India to Britain).....262
30.5 सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....262
राजनीतिक (Political).....262
द्विपक्षीय संस्थागत संलग्नता (Bilateral Institutional Engagements).....263
रक्षा (Defence).....263
परमाणु सहयोग (Nuclear Cooperation).....264
आतंकवाद और चरमपंथ (Terrorism and Extremism).....264
साइबर सुरक्षा (Cyber Security).....264
आर्थिक (Economic).....264
द्विपक्षीय व्यापार (Bilateral Trade).....264
निवेश (Investments).....265
निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम (Steps Needed to Boost Investment).....265
शिक्षा (Education).....265
जलवायु और पर्यावरण (Climate and Environment).....266
स्वास्थ्य (Health).....266
संस्कृति (Culture).....266
लोगों के मध्य जुड़ाव (People to People Contact).....266
30.6 प्रमुख पहलें (Major initiatives).....266
30.7 संबंधों में चुनौतियाँ (Challenges in Relations).....267
वीज़ा संबंधी (Visa Issues).....267
भूतलक्षी कराधान (Retrospective Taxation).....267
प्रत्यर्पण (Extradition).....268
ब्रेक्जिट (Brexit).....268
30.8 चुनौतियों से निपटने के लिए उठाए गए कदम (Steps taken to Address the Challenges).....268
30.9 मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement).....269
विवादास्पद मुद्दे (Contentious Issues).....269
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि (Background of India-UK Free Trade Agreement).....270
30.10 निष्कर्ष (Conclusion).....270
प्रमुख शब्दावली (Keywords).....270

अध्याय 31

भारत-अफ़्रीका संबंध (India-Africa Relations).....271
31.1 परिचय (Introduction).....271
31.2 भारत-अफ़्रीका मंच शिखर सम्मेलन (India-Africa Forum Summit).....271
31.3 राइज़िंग अफ़्रीका (Rising Africa).....272
31.4 अफ़्रीका-भारत संबंधों का महत्त्व (Significance of Africa-India Relations).....272
भू-रणनीतिक (Geo-strategic).....272
भू-आर्थिक (Geo-economic).....273
भू-राजनीतिक (Geopolitical).....273
31.5 अफ़्रीका में भारत और चीन (India and China in Africa).....274
अफ़्रीका में चीन की उपस्थिति (China's Presence in Africa).....274
अफ़्रीका में भारत की उपस्थिति (India's Presence in Africa).....274
31.6 भारत के लिए चुनौतियाँ और अवसर (Challenges and Opportunities for India).....275
चुनौतियाँ (Challenges).....275
अवसर (Opportunities).....275
31.7 सहयोग हेतु अन्य मंच (Other Forums of Cooperation).....276
31.8 आगे की राह (Way Forward).....276
31.9 निष्कर्ष (Conclusion).....277
मुख्य बिंदु (Keywords).....277

अध्याय 32

भारत और प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र (India and Pacific Island Nations) 278

32.1 परिचय (Introduction) 278

32.2 प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र (Pacific Island Nations: PINs) 278

32.3 भारत के लिए प्रशांत द्वीपीय राष्ट्रों का महत्त्व (Significance of Pacific Island Nations to India) 278

ऐतिहासिक (Historical) 278

भौगोलिक (Geographic) 279

रणनीतिक (Strategic) 279

आर्थिक (Economic) 279

32.4 इन क्षेत्रों में विकास की कमी के लिए उत्तरदायी कारण (Reasons of Development Deficit in These Regions) 279

32.5 भारत के लिए अवसर (Opportunities for India) 280

कृषि और संबद्ध क्षेत्र (Agriculture and Allied Sectors) 280

विनिर्माण और खनिज अन्वेषण (Manufacturing and Minerals Exploration) 280

सेवा क्षेत्रक (Services Sector) 280

जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन (Climate Change and Disaster Management) 280

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (Space Technology) 280

संस्कृति और प्रवासी (Culture and Diaspora) 281

32.6 हालिया पहलें (Recent Initiatives) 281

32.7 भारत के लिए चुनौतियाँ (Challenges for India) 282

32.8 आगे की राह (Way Forward) 282

32.9 निष्कर्ष (Conclusion) 282

प्रमुख शब्द (Keywords) 282

इकाई –IV: क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह

अध्याय 33

क्षेत्रवाद और बहुपक्षवाद (Regionalism and Multilateralism) 284

33.1 क्षेत्रवाद (Regionalism) 284

नव-क्षेत्रवाद का उदय (The Rise of New Regionalism) 284

क्षेत्रवाद के विकास के कारण (Reasons for Growth of Regionalism) 285

क्षेत्रवाद, स्वायत्ततावाद और राष्ट्रवाद (Regionalism, Autonomism and Nationalism) ... 285

33.2 बहुपक्षवाद (Multilateralism) 286

बहुपक्षवाद के विकास के कारण (Reasons for Growth of Multilateralism) 287

क्षेत्रवाद बनाम बहुपक्षवाद (Regionalism vs Multilateralism) 287

बहुपक्षवाद का भविष्य (Future of Multilateralism) ... 287

33.3 आगे की राह (Way Forward) 288

अध्याय 34

क्षेत्रीय समूह (Regional Groupings) 289

34.1 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगसंगठन (The South Asian Association for Regional Cooperation: SAARC) 289

सदस्यता (Membership) 289

शिखर सम्मेलन (Summits) 289

उद्देश्य (Objectives) 289

संरचना और प्रक्रिया (Structure and Process) 289

सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation) 290

महत्त्व (Significance) 290

घटनाक्रम (Developments) 290

नवीनतम घटनाक्रम (Latest Developments) 291

सार्क का पुनरुत्थान (Revival of SAARC) 291

सार्क की घरेलू चुनौतियाँ (Domestic Challenges of SAARC) 292

विश्लेषण (Analysis) 292

आगे की राह (Way Forward) 293

34.2 बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) 293

सदस्यता (Membership) 294

शिखर सम्मेलन (Summits) 294

उद्देश्य (Objectives) 294

संस्थापक सिद्धांत (Founding Principles) 294

बिम्सटेक का महत्त्व (Importance of BIMSTEC) 295

भारत के लिए महत्त्व (Importance for India) 295

घटनाक्रम (developments) 295

मुद्दे और चुनौतियाँ (Issues and Challenges) 295

आगे की राह (Way Forward) 296

34.3 ब्रिक्स (BRICS) 296
सदस्यता (Membership).....297
ब्रिक्स की विशेषताएँ (Features of BRICS).....297
सिद्धांत (Principles).....297
ब्रिक्स का महत्त्व (Importance of BRICS).....297
ब्रिक्स के अंतर्गत विकास (Developments in BRICS).....298
न्यू डेवलपमेंट बैंक (ब्रिक्स बैंक) [(New Development Bank (BRICS Bank)] 298
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (Summits of BRICS).....298
उद्देश्य (Objectives).....299
14वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (14th BRICS Summit)..300
15वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (15th BRICS Summit)..300
BRICS विस्तार (BRICS EXPANSION).....300
विस्तार का निर्णय (The decision to Expand).....301
विस्तार की आवश्यकता (The Need for Expansion).301
हाल ही में किए गए विस्तार का महत्त्व (Significance of the recent Expansion).....301
BRICS विस्तार और BRICS मुद्रा के शुभारंभ के लाभ (Benefits of BRICS Expansion and Launch of BRICS Currency).....302
चुनौतियाँ (Challenges).....302
आगे की राह (Way forward).....303

34.4 दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (South Asia Subregional Economic Cooperation: SASEC)..303
सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....304
दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग से संबंधित मुद्दे (Issues with SASEC).....304
दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के लिए सुझाव (Suggestions for SASEC).....304
भारत और दक्षिण एशिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (India and SASEC).....304

34.5 शंघाई सहयोग संगठन [Shanghai Cooperation Organisation - SCO]...305
सदस्यता (Membership).....306
शिखर सम्मेलन (Summits).....306
समरकंद शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन (Samarkand SCO Summit).....306
एससीओ के उद्देश्य (Objectives of SCO).....306
संगठनात्मक संरचना (Organisational Structure).....306
सहयोग के क्षेत्र (Areas of Cooperation).....307
भारत की सदस्यता (India's Membership).....307
SCO में भारत के लिए चुनौतियाँ (Challenges for India in SCO).....308
SCO का विश्लेषण (Analysis of SCO).....308
हालिया शिखर सम्मेलन (Recent Summit).....309
आगे की राह (Way Forward).....310
कीवर्ड (Keywords).....310

34.6 I2U2 310

अध्याय 35

भारत और हिंद महासागर
(India and Indian Ocean).....313

35.1 परिचय (Introduction).....313

35.2 हिंद महासागर का महत्त्व (Significance of Indian Ocean).....313
आर्थिक (Economic).....313
गहरे समुद्री अन्वेषण (Deep Sea Exploration).....314
सामरिक और सुरक्षा (Strategic and Security).....314

35.3 हिंद महासागर में भारत की भूमिका (Role of India in Indian Ocean).....314
शुद्ध सुरक्षा प्रदाता (Net Security Provider).....314
मानवीय और आपदा राहत अभियान (Humanitarian and Disaster Relief Operations).....315
ब्लू इकॉनमी (Blue Economy).....315
प्रवासी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान (Diaspora and Cultural Exchanges).....315
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (Space Technology).....315

35.4 हिंद महासागर नीति (Indian Ocean Policy).....315

35.5 हिंद महासागर में क्षेत्रीय समूह (Regional Groupings in Indian Ocean).....316

35.6 भारत के समक्ष चुनौतियाँ (Challenges for India).....316
समुद्री सुरक्षा (आतंकवाद, समुद्री डकैती और मादक पदार्थों की तस्करी) [Maritime Security (Terrorism, Piracy and Drug Trafficking)].....316
शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत – एक महत्त्वपूर्ण विश्लेषण (India as a Net Security Provider – A Critical Analysis).....316
जलवायु परिवर्तन और हिंद महासागर क्षेत्र [Climate Change and Indian Ocean Region (IOR)].....317

हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति (China's Presence in Indian Ocean).....317
पाकिस्तान द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ (Challenges Posed by Pakistan).....317
रूस IORA में संवाद भागीदार के रूप में शामिल (Russia Joins IORA as Dialogue Partner).....318
35.7 आगे की राह (Way Forward).....318
35.8 निष्कर्ष (Conclusion).....318
मुख्य शब्दावली (Keywords).....319

अध्याय 36

बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाएँ (Multilateral Export Control Regimes).....320
36.1 परिचय (Introduction).....320
36.2 परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group- NSG).....320
सदस्यता (Membership).....320
सदस्यता मानदंड (Membership Criteria).....320
लक्ष्य (Goals).....321
रक्षोपाय (Safeguards).....321
दोहरे उपयोग पर नियंत्रण (Dual-use Controls).....321
परमाणु अप्रसार संधि (Non-Proliferation Treaty- NPT).....322
NPT और NSG.....322
चीन का विरोध (China's Opposition).....322
भारत के लिए NSG की सदस्यता का महत्त्व (Significance of NSG Membership for India)....323
भारत की सदस्यता के अनुकूल कारक (Factors in Favour of India's Membership).....323
36.3 मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime: MTCR).....323
भारत और MTCR (India and MTCR).....324
36.4 वासेनार अरेंजमेंट (Wassenaar Arrangement: WA).....324
36.5 ऑस्ट्रेलिया समूह (Australia Group).....324
सदस्यता के लाभ (Advantages of Membership)...325
प्रमुख शब्दावलियाँ (Keywords).....325

अध्याय 37

वैश्विक शासन संस्थाएँ (Global Governance Institutions).....326
37.1 संयुक्त राष्ट्र (United Nations).....326
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Perspective).....326
समकालीन प्राथमिकताएँ (Contemporary Priorities) 326
37.2 वैश्विक शासन और वैश्विक कॉमन्स का शासन (Global Governance and Governance of Global Commons).....327
वैश्विक शासन और सतत् विकास (Global Governance and Sustainable Development)....327
ग्लोबल कॉमन्स (वैश्विक साझी संपदा) का शासन (Governance of Global Commons).....328
विकास के लिए वैश्विक प्रशासन एवं वैश्विक भागीदारी (Global Governance and Global Partnership for Development).....329
निष्कर्ष (Conclusion).....329
37.3 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (United Nations Human Rights Council).....330
UNHRC से संबंधित समस्याएँ (Problems with UNHRC).....330
भारत और UNHRC (India and UNHRC).....331
37.4 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice- ICJ).....331
ICJ से संबंधित समस्याएँ (Problems with ICJ).....331
समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव (Suggestions to Address Problems).....332
भारत और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (India and ICJ).....332
37.5 अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court).....332
ICC का गठन (Formation of the ICC).....332
निकाय की प्रकृति (Nature of the Body).....332
ICC के साथ समस्याएँ (Problems with ICC).....333
समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव (Suggestions to Address Problems).....333
भारत और ICC (India and ICC).....333
प्रमुख शब्द (Keywords).....333

अध्याय 38

भारत और प्रवासी (India and Diaspora).....334
38.1 परिचय (Introduction).....334
38.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background).....334
प्राचीन एवं मध्यकालीन (Ancient and Medieval).....334
औपनिवेशिक काल (Colonial Period).....334
उत्तर-औपनिवेशिक काल (Post-Colonial Period).....334
38.3 प्रवासी नीति (Diaspora Policy).....335
सक्रिय पृथक्करण (Active Dissociation).....335
प्रवासी नीति का नया युग (New Era for Diaspora Policy).....335

38.4 रणनीतिक प्रगति (Strategic Advances).....335
38.5 आर्थिक शक्ति (Economic Strength).....336
38.6 प्रवासी और भारतीय हित (Diaspora and Indian Interests).....336
38.7 भारतीय प्रवासी समुदाय के समक्ष आने वाली समस्याएँ (Issues Faced by Indian Diaspora).....337
पश्चिम एशिया (West Asis).....337
अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन (US, Canada & UK) ...337
दोहरी नागरिकता (Dual Citizenship) 337
38.8 आगे की राह (Way Forward).....337
मुख्य शब्दावली (Keywords).....337

अध्याय 39

समसामयिक घटनाक्रम (Contemporary Developments) ..338
39.1 चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (QUAD) 338
क्वाड (QUAD) के गठन की पृष्ठभूमि (Backdrop of QUAD Formation) 338
भारत के लिए क्वाड (QUAD) का महत्त्व (Importance of QUAD for India) 338
क्वाड (QUAD) के समक्ष चुनौतियाँ (Challenges Before QUAD) 338
हालिया शिखर सम्मेलन (Recent Summit) 339
व्यक्त की गई चिंताएँ (Concerns expressed).....340
39.2 वैक्सीन कूटनीति (Vaccine Diplomacy) 340
भारत से वैक्सीन प्राप्त करने वाले देश (Countries Getting Vaccines from India) 340
चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति (Supply in Phased Manner).....340
महत्त्व (Significance) 341
अन्य पिछले प्रयास (Other Previous Efforts).....341
39.3 AUKUS गठबंधन (AUKUS Alliance) 341
निहितार्थ (Implications) 341
39.4 रूस-यूक्रेन संकट (Russia-Ukraine Crisis).....341
विभिन्न देशों का रुख (Stand of Various Nations) ..342
संघर्ष से जुड़े प्रमुख मुद्दे (Major Issues Surrounding the Conflict) 343
UN चार्टर का उल्लंघन (Violation of the UN Charter) 344
भारत पर प्रभाव (Impact on India) 344
भारत के लिए सबक (Lessons for India) 345
निष्कर्ष (Conclusion).....345
39.5 चीन-ताइवान मुद्दा और एक चीन नीति (China-Taiwan Issue and One China Policy) 345
39.6 भारत और भू-राजनीति (India and Geopolitics).....346
गुटनिरपेक्ष आंदोलन [Non-Aligned Movement (NAM)] 346
बदलती भू-राजनीति (Changing Geopolitics) 347
हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) 347
हिंद-प्रशांत का महत्त्व (Significance of Indo-Pacific) 347
39.7 भारत की आर्कटिक नीति (India's Arctic Policy) 347
39.8 भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 (Indian Antarctic Bill, 2022) 348
39.9 न्यू स्टार्ट संधि (New START Treaty) 349
39.10 इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए [Israel Signed a Free Trade Deal with the United Arab Emirates (UAE)] 349
39.11 GLOBSEC 2022 ब्रातिस्लावा फोरम में भारत का रुख (India's Stand at GLOBSEC 2022 Bratislava Forum).....349
39.12 फ़िनलैंड और स्वीडन के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का प्रवेश प्रोटोकॉल (NATO's Accession Protocol for Finland and Sweden) 350
39.13 सामूहिक विनाश के हथियार विधेयक (Weapons of Mass Destruction (WMD) Bill) 350
39.14 अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे का संचालन आरंभ (INSTC Operationalised) 350
39.15 OPEC प्लस (OPEC Plus) 350
39.16 खनिज सुरक्षा साझेदारी (Minerals Security Partnership) 351
39.17 फाइव आईज़ एलायंस (Five Eyes Alliance).....351
सामान्य कारण (Common Cause) 352
39.18 भारत-मध्य पूर्व-यूरोप मेगा आर्थिक गलियारा (India-Middle East-Europe Mega Economic Corridor- IMECE) 352
संदर्भ (Context) 352
IMECE के बारे में (About).....352
गलियारा (Corridor).....352
सदस्य (Members) 352
उद्देश्य (Purpose) 352
भारत के लिए महत्त्व (Importance for India).....353
भारत के लिए भौगोलिक लाभ (Geographical Advantage for India).....353

वैश्विक अवसंरचना निवेश हेतु साझेदारी क्या है? (What is the Partnership for Global Infrastructure Investment- PGII) 353
विकल्प की आवश्यकता (Need for an alternative)..354
वर्तमान समय तक हुई प्रगति (Progress so far).....354
महत्त्व (Importance) 355
39.19 वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (Global Biofuels Alliance).....355
संदर्भ (Context) 355
देश और संगठन (Countries and Organizations)...355
संस्थापक सदस्य (Founding Members) 355
जैव ईंधन उत्पादन और भारत के लक्ष्य (Biofuel Production and India's Targets) 355
उद्देश्य (Purpose) 355
केंद्र (Focus).....355
महत्त्व (Significance).....355
39.20 वैश्विक दक्षिण (Global South).....356
संदर्भ (Context) 357
ग्लोबल साउथ क्या है (What is Global South)?.....357
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background) 357
वैश्विक दक्षिण की विशेषताएँ (Features of the Global South) 357
वर्गीकरण की आवश्यकता (Need for Classification).....357
यूक्रेनी युद्ध के बीच वैश्विक दक्षिण (Global South amid Ukrainian War).....357
वैश्विक दक्षिण का महत्त्व (Significance of the Global South).....357
समेकन करने की दिशा में चुनौतियाँ (Challenges for Consolidation).....357
निष्कर्ष (Conclusion).....358
39.21 जी-20 (G20) 358
जी-20 क्या है (What is G-20)?.....358
जी-20 भारत अध्यक्षता (G-20 India Presidency)....358
जी-20 अध्यक्षता का महत्त्व (Importance of G-20 Presidency).....359
मुख्य परिणाम (Key outcomes).....359
अवसर की चूक (Missed Opportunity) 360

इकाई I

भारत एवं उसके पड़ोसी देश

1. **भारत की विदेश नीति : सिंहावलोकन** (India's Foreign Policy: An Overview) 2
2. **भारत और पड़ोसी देश** (India and Neighbours) 26
3. **भारत–बांग्लादेश** (India-Bangladesh) 32
4. **भारत–पाकिस्तान** (India-Pakistan) 45
5. **भारत–श्रीलंका** (India-Sri Lanka) 55
6. **भारत–अफ़ग़ानिस्तान** (India-Afghanistan) 64
7. **भारत–चीन** (India-China) 72
8. **भारत–भूटान** (India-Bhutan) 91
9. **भारत–नेपाल** (India-Nepal) 95
10. **भारत–म्यांमार** (India-Myanmar) 102
11. **भारत–मालदीव** (India-Maldives) 108
12. **भारत–मॉरीशस** (India-Mauritius) 113

अध्याय

1

भारत की विदेश नीति : सिंहावलोकन
(India's Foreign Policy: An Overview)

1.1 परिचय (Introduction)

विदेश नीति वह तंत्र है, जिसका उपयोग राष्ट्रीय सरकारें अन्य देशों के साथ अपने राजनयिक संबंधों और पारस्परिक प्रभावों को निर्देशित करने के लिए करती हैं। किसी राज्य की विदेश नीति उसके मूल्यों और लक्ष्यों को दर्शाती है तथा वैश्विक क्षेत्र में उसके राजनीतिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करती है।

कई विदेश नीतियों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे किसी देश के, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं अन्य देशों के नागरिकों के साथ संबंध निर्धारित होते हैं।

विदेश नीतियाँ कई कारकों द्वारा विकसित और प्रभावित होती हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भौगोलिक, वित्तीय, राजनीतिक आदि अनेक क्षेत्रों में देश की परिस्थितियाँ।
- अन्य देशों का व्यवहार और विदेश नीतियाँ।
- अधिक व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और मामलों की स्थिति। (उदाहरण के लिए, क्या युद्ध या अशांति की स्थिति है? क्या ऐसे व्यापार गठबंधन हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए?)।
- उन्नति की योजनाएँ, जैसे आर्थिक उन्नति या तकनीकी उन्नति।

राजनीतिज्ञ और राजनयिक निकाय विदेश नीति से निर्देशित होते हैं। वे दो देशों की साझा चुनौतियों से निपटने, उनमें स्थिरता को बढ़ावा देने और साझा हितों की रक्षा हेतु मिलकर कार्य कर सकते हैं।

किसी देश की विदेश नीति सामान्यत: उसकी घरेलू नीति के साथ मिलकर कार्य करती है। घरेलू नीति सरकारी नीति का दूसरा रूप है, जो आंतरिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करती है। दोनों नीतियाँ एक-दूसरे की पूरक होती हैं और देश की सीमाओं के भीतर और बाहर दोनों जगह उसकी स्थिति को सुदृढ़ करती हैं।

संक्षेप में, विदेश नीति एक ऐसा ढाँचा है, जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार बाह्य देशों के साथ अपने संबंधों को विभिन्न स्वरूपों, अर्थात् द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय या वैश्विक रूप में संचालित करती है।

कूटनीति (Diplomacy) अपने आप में एक व्यवसाय, कौशल और कला है। इसका उद्देश्य किसी देश की विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शेष विश्व के साथ उस देश के संबंधों को प्रबंधित करना है। सामान्य रूप में कूटनीति राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक हो सकती है और आदर्श रूप से इसे एकसाथ मिलकर काम करना चाहिए। एक नियम के रूप में कूटनीति स्थापित राजनयिक संबंधों और तंत्रों के माध्यम से आगे बढ़ाई जाती है। यह हमेशा पारदर्शी और सार्वजनिक लोगों की जानकारी में हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कई बार इसे गुप्त रूप से या अनौपचारिक ट्रैक 1.5/ट्रैक 2 तंत्रों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है।

1.2 भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत (Objectives and Principles of India's Foreign Policy)

भारत की विदेश नीति के विविध उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों का मिश्रण प्राप्त करना हैं। भारत ने अपनी सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक उन्नति को प्राप्त करने के साथ-साथ सभी देशों एवं लोगों के लिए शांति, स्वतंत्रता, प्रगति और न्याय के लिए कार्य करने का प्रयास किया है।

भारत की विदेश नीति के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- इसका उद्देश्य देश की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा और बाह्य सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना है।
- इसका उद्देश्य विश्व शांति को बढ़ावा देना, सैन्य ख़तरों को रोकना या उनका प्रतिरोध करना, नि:शस्त्रीकरण की पहल का समर्थन करना, शांतिपूर्ण पड़ोस का प्रयास करना और युद्धों से बचने के लिए कार्य करना है।
- वैचारिक, राजनीतिक और अन्य मतभेद वाले देशों के बीच सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देना।
- अपनी विदेश नीति को बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों और राष्ट्रों के समान अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में निर्देशित करना।
- भारत के घरेलू विकास को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का लाभ उठाना।
- वैश्विक शासन के मामलों में भारतीय प्रतिनिधित्व और नेतृत्व को आगे बढ़ाना।

हालाँकि, मुख्य रूप से यह राष्ट्र के हितों की सुरक्षा से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए भारत के मामले में इसमें अग्रलिखित

विषय शामिल हैं: क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करना, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण, गैर-भेदभावपूर्ण वैश्विक व्यापार पद्धति, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए न्यायसंगत वैश्विक उत्तरदायित्व, समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक शासन के संस्थानों में सुधार, नि:शस्त्रीकरण, क्षेत्रीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय शांति आदि।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में निम्नलिखित सिद्धांतों ने भारत का मार्गदर्शन किया है:

- पंचशील
- गुटनिरपेक्षता (Non-alignment)
- उपनिवेशवाद विरोधी (Anti-colonialism), साम्राज्यवाद विरोधी (Anti-imperialism) और नस्लवाद विरोधी (Anti-racism)
- अन्य देशों के साथ मतभेदों का समाधान करने हेतु बल प्रयोग से बचने का सिद्धांत।
- संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य वैश्विक एवं क्षेत्रीय संगठनों को मज़बूत बनाना तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव और सहयोग के लिए उपयोगी उपकरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास करना।
- रणनीतिक साझेदारी (Strategic partnership)

संक्षेप में, भारत विदेश नीति के माध्यम से अपनी छवि एक शांतिप्रिय, परिपक्व, विधि का पालन करने वाले और भरोसेमंद देश के रूप में बनाना चाहता है। साथ ही राष्ट्रों के समूह में अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संपर्कों से लाभ उठाने का प्रयास भी करता है।

1.3 भारत की विदेश नीति का विकास (Evolution of India's Foreign Policy)

भारत की विदेश नीति का विकास मूल रूप से स्वतंत्रता-पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि के दौरान ही शुरू हो गया था। वर्ष 1921 में नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 'भारत के विदेशी संबंधों के इतिहास में एक मील का पत्थर' थी। यहाँ पहली बार, कांग्रेस ने विदेश नीति पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह कथन शामिल था कि "भारत की वर्तमान सरकार किसी भी तरह से भारतीय मत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है"। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने वर्ष 1927 में मद्रास में आयोजित अपने सत्र में एक और महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। इसमें ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप के बिना शेष विश्व के साथ भारत के बाह्य संबंधों को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। वास्तव में, भारत की विदेश नीति की नींव कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में रखी गई थी।

वर्ष 1921 से 1947 तक के कांग्रेस प्रस्तावों के मूल्यांकन से निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है;

- फ़ासीवाद के विकास में ख़तरों के प्रति गहन जागरूकता,
- सोवियत संघ की आकांक्षाओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण,
- विश्व में हर जगह पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्ति की निरंतरता या विस्तार की लगातार आलोचना, और
- सभी प्रकार के नस्लीय, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का संवेदनशील प्रदर्शन।

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात् ही भारत ने अपनी आवश्यकताओं और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार अपनी विदेश नीति विकसित करना प्रारंभ कर दिया। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की विदेश नीति के तहत विश्व के सभी देशों के साथ मित्रता और सहयोग के सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है, चाहे उनकी राजनीतिक व्यवस्था कुछ भी हो। विशेष रूप से पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार रहा है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित थी, क्योंकि भारत ने अपनी स्वतंत्रता उस समय हासिल की थी, जब शीत युद्ध का संकट पहले से ही विश्व पर मंडरा रहा था। इस युद्ध के परिणामस्वरूप विश्व को न केवल महाशक्तियों की शक्ति की राजनीति (Power Politics) का सामना करना पड़ा, बल्कि उसके परिणाम भी भुगतने पड़े। इसने स्वाभाविक रूप से भारत को अपनी विदेश नीति को गैर-हस्तक्षेप और गुटनिरपेक्षता के आधार पर तैयार करने के लिए प्रेरित किया, जो भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत बन गया।

जवाहरलाल नेहरू के अधीन विदेश नीति (Foreign Policy under Jawaharlal Nehru)

जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वावधान में भारत की विदेश नीति के विकास में निर्णायक और गतिशील भूमिका निभाई। नेहरू को भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता माना जाता है। 7 सितंबर, 1946 को नई दिल्ली से होने वाले एक प्रसारण में जवाहरलाल नेहरू ने आधारभूत नीति की रूपरेखा का विवरण दिया था, जिसमें उन्होंने विदेश नीति के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। इन लक्ष्यों में शामिल थे: उपनिवेशवाद और नस्लवाद का अंत, शक्ति के गुटों से स्वतंत्रता तथा चीन एवं एशियाई पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध।

नेहरू ने विदेश नीति की रूपरेखा यह घोषित करते हुए निर्धारित की, कि भारत हमेशा शक्ति की राजनीति से दूर रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि, "जहाँ भी स्वतंत्रता को ख़तरा हो या न्याय को ख़तरा हो या जहाँ आक्रमण हो, वहाँ हम तटस्थ नहीं हो सकते और न ही रहेंगे।" नेहरू संयुक्त राष्ट्र में भारत की अटूट आस्था को बढ़ाने में विश्वास करते थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि भारत को महाशक्तियों की शक्ति की राजनीति में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही।

"विश्व के राष्ट्रों और लोगों को हम शुभकामनाएँ भेजते हैं तथा शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में उनके साथ सहयोग करने का संकल्प लेते हैं।"

जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1947 में नई दिल्ली में संसद भवन में अपने "ट्रिस्ट विद डेस्टिनी" भाषण में

गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक विचार है। इसका अर्थ यह था कि भारत अपने हितों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता को कायम रखेगा। संकट में घिरे किसी भी राष्ट्र को समर्थन देने की कोई पूर्व प्रतिबद्धता नहीं थी।

नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत को घरेलू मोर्चे पर निर्धनता उन्मूलन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शीत युद्ध के मुद्दे तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक संवृद्धि और राजनीतिक स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए भारत को शांति और स्थिरता की अवधि की आवश्यकता थी। इस प्रकार, यह माना जा रहा था कि किसी भी प्रमुख शक्ति के साथ गठबंधन करने से यह प्राथमिक लक्ष्य विफल हो जाएगा और भारत शीत युद्ध के टकराव-क्षेत्र में बदल जाएगा। राष्ट्रीय एकीकरण और विकास के कार्य को देखते हुए, भारत अपनी ऊर्जा और दुर्लभ संसाधनों को हथियारों के वर्चस्व की दौड़ में व्यय करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसलिए नेहरू के नेतृत्व में भारत ने निम्नलिखित नीतियों का अनुपालन किया:

नेहरू और पंचशील (Nehru and Panchsheel)

'पंचशील' शब्द का अर्थ है, 'पाँच गुण (Five Virtues)'। ये गुण प्राचीन बौद्ध धर्मग्रंथों में वर्णित हैं, जो भारतीय भिक्षुओं के व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करते थे। नेहरू के अधीन, यह विचार विश्व के राष्ट्रों के मध्य संबंधों को निर्देशित करने वाला एक केंद्रीय विषय बन गया था।

भारत-चीन संबंधों को संचालित करने के लिए भी यही सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। इस विचार को दोनों देशों के बीच एक व्यापार समझौते में शामिल किया गया था। इस समझौते से तिब्बत पर उनके द्विपक्षीय व्यापार संचालन को सुव्यवस्थित किया गया। इसके आधार पर, भारत और चीन अपने संबंधों के संचालन में निम्नलिखित पाँच सिद्धांतों का अनुपालन करने पर सहमत हुए थे:

- एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान,
- पारस्परिक अनाक्रमण,
- पारस्परिक अहस्तक्षेप,
- समानता और पारस्परिक लाभ, तथा
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

पंचशील समझौते में निहित सिद्धांतों ने बाद में न केवल दोनों देशों के बीच, बल्कि अन्य सभी देशों के साथ भी उनके संबंधों को दिशा दी। इसे विश्व में शांति और सुरक्षा की नींव रखने के रूप में देखा गया। ऐसा माना जा रहा था कि इससे नव स्वतंत्र देशों को आवाज़ मिलेगी, साथ ही विश्व में युद्ध की संभावना भी कम होगी।

वर्ष 1955 में 29 अफ्रीकी-एशियाई देशों का बांडुंग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। बांडुंग सम्मेलन के दौरान पंचशील सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के दस सिद्धांतों में शामिल किया गया था। इन सिद्धांतों को घोषणा-पत्र में शामिल किया गया था। वर्ष 1957 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इन सिद्धांतों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल सिद्धांतों के रूप में भी स्वीकार किया गया।

मूलत:, ये सिद्धांत बल प्रयोग न करना, सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रतीक हैं। ये सभी देशों को अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाए रखते हुए, सहयोग के साथ शांति और समृद्धि की दिशा में कार्य करने में सक्षम बनाते हैं।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Alignment Movement)

गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा गठित किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल न होकर विदेशी मामलों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता बनाए रखना था। गुटनिरपेक्षता न तो तटस्थता, न ही गैर-हस्तक्षेप और न ही अलगाववाद था। यह एक गतिशील अवधारणा थी, जिसका अर्थ किसी भी सैन्य गुट के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना और प्रत्येक मामले के महत्त्व के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र रुख अपनाना था।

नेहरू गुटनिरपेक्षता को विदेश नीति के क्षेत्र में भारत की स्वतंत्रता की गारंटी मानते थे। उनके अनुसार, विश्व के किसी भी गुट में शामिल होने का अर्थ केवल एक ही बात होगी, "किसी विशेष प्रश्न के बारे में अपना दृष्टिकोण त्यागकर, दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण को अपनाना, उसे खुश करना और उसका समर्थन प्राप्त करना।"

भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की परिकल्पना पाँच नेताओं - जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्देल नासिर (मिस्र), सुकर्णो (इंडोनेशिया) क्वामे नक्रूमा (घाना) और यूगोस्लाविया के जोसिप ब्रोज टीटो ने की थी। NAM का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नव स्वतंत्र देशों का एक समूह था। उन्होंने पूर्व औपनिवेशिक

स्वामियों के आदेशों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तथा अंतर्राष्ट्रीय सरोकार के मुद्दों पर अपने स्वयं के निर्णय के अनुसार कार्य करने का निर्णय लिया था।

NAM के संस्थापक: जवाहरलाल नेहरू (भारत), क्वामे नक्रूमा (घाना), गमाल अब्देल नासिर (मिस्र), सुकर्णो (इंडोनेशिया), जोसिप ब्रोज टीटो (यूगोस्लाविया)

NAM भारत के लिए मुख्यतः दो कारणों से महत्त्वपूर्ण था:

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भारत को अपने हितों की पूर्ति के आधार पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेने की अनुमति दी।
- इससे भारत को दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन कायम करने में मदद मिली, क्योंकि कोई भी महाशक्ति भारत पर दबाव नहीं बना सकी, न ही उसे प्रभावहीन समझ सकी।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इस विचारधारा को प्रतिबिंबित किया कि एक संप्रभु राष्ट्र, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, अपने स्वयं के आकलन और आवश्यकता के आधार पर एक स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकता है। यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण की आवश्यकता को भी मान्यता प्रदान करता है, जो उभरते देशों की संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उन्हें अधिक हिस्सेदारी दिए जाने की माँग की पृष्ठभूमि में आज भी बहुत प्रासंगिक है।

चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संघर्षों एवं दक्षिण एशिया से जुड़े कुछ प्रमुख संबंधों में बड़े बदलावों के बावजूद नेहरू की गुटनिरपेक्षता नीति जारी रही। संयुक्त राज्य अमेरिका-पाकिस्तान गठबंधन के गठन और पतन, भारत एवं सोवियत संघ के मध्य घनिष्ठ संबंधों के विकास और चीन-भारत संबंधों के दौरान, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति और विश्व शांति के लिए अपने समर्थन को बनाए रखा।

कश्मीर मुद्दा (Kashmir Issue)

भारत के विदेश संबंधों में कश्मीर सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में शीत युद्ध को जन्म दिया। इसके परिणामस्वरूप सैन्य हथियारों पर अत्यधिक व्यय हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद से, तथा वर्ष 1962 के बाद तो यह मुद्दा और भी अधिक प्रबल हो गया। कश्मीर भारत की रक्षा में एक प्रमुख कारक बना हुआ है।

कश्मीर मुद्दे पर नेहरू का दृष्टिकोण तब भी सामने आया, जब यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र को भेजा गया। उस समय संयुक्त राष्ट्र एक नवजात और प्रयोगात्मक संगठन था, जो पश्चिमी शक्तियों के पक्ष में अधिक था। संयुक्त राष्ट्र को यह मुद्दा भेजे जाने पर, संविधान सभा में मार्च 1948 में नेहरू ने कहा कि "संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् को यह मुद्दा भेजना हमारी आस्था का कार्य था, क्योंकि हम विश्व व्यवस्था और विश्व सरकार के क्रमिक कार्यान्वयन में विश्वास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि कश्मीर विवाद को भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए एवं जनमत संग्रह की भी बात की गई। हालाँकि, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित जनमत संग्रह या कश्मीर मुद्दे को हल करने में पाकिस्तान द्वारा वांछित किसी भी बाह्य हस्तक्षेप को स्वीकार करने के विकल्पों को ख़ारिज कर दिया। चूँकि इस जटिल मुद्दे को हल करने में कोई सफलता नहीं मिली और सुरक्षा परिषद् के प्रस्ताव पर नाराज़गी के कारण, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक अघोषित युद्ध छेड़कर कश्मीर को हासिल करने का फ़ैसला किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अशांत साधनों का सहारा लेने का संकल्प लिया।

भारत-चीन संबंध और युद्ध (Indo-China Relation and War)

नेहरू का मानना था कि भारत और चीन में बहुत कुछ समानता है, क्योंकि दोनों देशों ने औपनिवेशिक शक्तियों के कारण कष्ट झेले हैं, साथ ही निर्धनता उन्मूलन और संवृद्धि के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए, उन्हें यह आशा थी कि दोनों देश एशिया के विकास में सहयोग करेंगे। अपनी ओर से, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में चीन के प्रतिनिधित्व के लिए आवाज़ उठाई। भारत ने कोरियाई युद्ध में चीन को एक आक्रामक राष्ट्र घोषित करने के अमेरिकी रुख का समर्थन नहीं किया।

तिब्बत का संकट (Tibetan Crisis)

वर्ष 1949 की चीनी क्रांति के पश्चात् चीन तिब्बत क्षेत्र का विलय करना चाहता था और इसे चीन का अभिन्न अंग मानता था। वर्ष 1950 में चीन ने इस क्षेत्र के पूर्वी हिस्से पर हमला किया और चामडो क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया। भारत ने इस आक्रमण का विरोध किया, उसने तिब्बत के अनुरोध पर मध्यस्थता की पेशकश भी की, जिसे चीन ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह उसका घरेलू मामला है।

पंचशील समझौते (1954) के तहत भारत ने स्वेच्छा से तिब्बत पर अपने सैन्य, संचार और डाक तथा अन्य अधिकार छोड़ दिए थे। ये अधिकार उसे वर्ष 1904 की आंग्ल-तिब्बत संधि के अनुसार अंग्रेजों से विरासत में मिले थे। भारत ने तिब्बत क्षेत्र पर चीन के दावे को मान्यता दी। उस समय चीन ने भारत को यह आश्वासन भी दिया था कि तिब्बत को और अधिक स्वायत्तता दी जाएगी, यद्यपि प्रतिबद्धता अभी भी पूरी नहीं हुई है।

वर्ष 1962 चीन का आक्रमण (1962 Chinese Attack)

नेहरू जानते थे कि वर्ष 1949 की चीनी क्रांति एक मौलिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही, वे चीन से संभावित ख़तरे से भी पूर्णत: अनभिज्ञ नहीं थे, क्योंकि नवंबर 1959 में लोकसभा में अपने भाषण में उन्होंने कहा था, "हम इतिहास से इतना परिचित हैं कि हम समझ सकते हैं कि एक मज़बूत चीन सामान्य तौर पर एक विस्तारवादी चीन होता है।" वर्ष 1962 का भारत-चीन युद्ध एक सीमा विवाद था, जिसकी परिणति युद्ध के रूप में हुई।

इस विवाद के दो कारण थे:

- **पहला,** तिब्बत पूर्व में एक बफ़र राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन चीन द्वारा उस पर कब्ज़ा कर लेने से सीमा मुद्दा जटिल हो गया।
- **दूसरा,** ब्रिटिश काल में भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा द्वारा किया जाता था। चीन ने इस रेखा को मान्यता देने से इनकार कर दिया।

पंचशील समझौते के बाद भारत को यह आशा थी कि मैकमोहन रेखा के माध्यम से सीमा विवाद सुलझ जाएगा, लेकिन ये कोशिशें नाकाम रहीं। सितंबर 1957 में भारत सरकार को ज्ञात हुआ कि चीन का 1200 किलोमीटर लंबा सैन्य राजमार्ग अक्साई चिन से होकर गुज़रता है। चीन ने अपने मानचित्र में इस क्षेत्र को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया। भारत ने इस आक्रामकता का विरोध किया। बाद में चीन ने दलाई लामा को शरण देने के भारत के फ़ैसले का विरोध किया। इन सीमा विवादों के चलते आख़िरकार वर्ष 1962 में युद्ध हुआ, जब चीन ने अक्साई चिन और उत्तर-पूर्व सीमांत एजेंसी (NEFA) दोनों पर तीव्र और व्यापक हमला किया। भारत ने चीन के उद्देश्य का आकलन करने में भी गलती की। हालाँकि चीन ने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के विरोध के बाद तेज़ी से वापसी की, लेकिन अक्साई चिन को अपने पास बरकरार रखा और NEFा को भारत के नियंत्रण में छोड़ दिया।

नेहरू को चीन के इरादों का सही आकलन करने में विफल रहने के कारण अपने पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद भारत की विदेश और सुरक्षा नीति में एक निश्चित बदलाव आया। दो वर्ष के भीतर, चीन ने परमाणु परीक्षण किया और भारत को रक्षा निवेश बढ़ाना पड़ा। इस प्रकार, भारत का परमाणु परीक्षण पाकिस्तान और चीन दोनों से उत्पन्न ख़तरे का परिणाम था। साथ ही, युद्ध ने भारत-चीन संघर्ष को वैश्विक शीत युद्ध का हिस्सा बना दिया, क्योंकि भारत ने सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए और चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों में सुधार किया। इस प्रकार, युद्ध ने भारत-चीन संबंधों को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया और संबंधों को सामान्य होने में कई वर्ष लग गए।

लाल बहादुर शास्त्री के अधीन विदेश नीति
(Foreign Policy under Lal Bahadur Shastri)

जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री ने मुख्य रूप से नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति को जारी रखा, लेकिन सोवियत संघ के साथ भी घनिष्ठ संबंध स्थापित किए।

सिरिमावो-शास्त्री समझौता (Sirimavo-Shastri Pact: 1964)

तत्कालीन सीलोन (वर्तमान में श्रीलंका) में भारतीय तमिलों के मुद्दे को सुलझाने के लिए, लाल बहादुर शास्त्री ने वर्ष 1964 में सीलोन के प्रधानमंत्री सिरिमावो आर.डी. भंडारनायके के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा गया, क्योंकि इसने भारत और सीलोन के मध्य लगातार चल रहे मतभेदों को समाप्त किया। इस समझौते के अनुसार 5,25,000 भारतीय तमिलों को वापस भारत भेजा जाना था, जबकि 3,00,000 को श्रीलंका की नागरिकता दी जानी थी। इस समझौते के प्रावधान 31 अक्टूबर, 1981 तक संपन्न किए जाने थे। हालाँकि, वर्ष 1982 में, भारत ने नागरिकता के लिए किसी भी अन्य आवेदन को स्वीकार करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वर्ष 1964 का समझौता अब समाप्त हो चुका है।

चीन का परमाणु परीक्षण (China's Nuclear Explosion- 1964)

शास्त्री जी के समय में चीन ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। इस संदर्भ में तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह परीक्षण पूर्ण रूप से चीनी लोगों को अमेरिका के परमाणु ख़तरे से बचाने के लिए था। हालाँकि चीन ने परमाणु हथियार के "पहले उपयोग न करने" की नीति की घोषणा की, फिर भी इसने न केवल भारत में, बल्कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के अन्य देशों में भी असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर दी थी। हालाँकि, शास्त्री जी के समय में, परमाणु परीक्षण के समर्थकों ने भारत पर भी परमाणु हथियार बनाने के लिए दबाव डाला। इस प्रकार, परमाणु हथियार नीति के मामले में नेहरू के युग का प्रभाव इस समय से कम होने लगा था।

भारत-पाकिस्तान युद्ध (India-Pakistan War - 1965)

वर्ष 1965 का युद्ध भारत के विदेशी संबंधों के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम माना जाता है, क्योंकि यह युद्ध नेहरू के बाद के दौर में हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। वास्तव में, वर्ष 1965 का युद्ध, जिससे भारत-पाक संबंधों में सुधार का मार्ग प्रशस्त करने की उम्मीद की जा रही थी, कश्मीर समस्या को हल करने में विफल रहा।

वर्ष 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध एक अघोषित युद्ध था। इस युद्ध का एक मुख्य कारण कश्मीर का मुद्दा था, क्योंकि पाकिस्तान इस मुद्दे को फिर से उठाने की माँग कर रहा था और भारत का कहना था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, यह एक स्पष्ट तथ्य है। युद्ध के निम्नलिखित कारण थे:

- वर्ष 1965 में कश्मीर में स्थिति अधिक अस्थिर हो गई थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला के समर्थकों और अन्य कारकों ने घाटी क्षेत्र में अशांति उत्पन्न कर दी थी। इसलिए, पाकिस्तानी नेतृत्व ने इसे हस्तक्षेप के लिए सही समय माना।
- इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान के पास अमेरिका से प्राप्त उन्नत सैन्य हथियार भी थे। पाकिस्तान वर्ष 1962 के चीन-भारत युद्ध की पराजय के बाद भारत द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किए जाने से पहले ही हमला करना चाहता था।
- पाकिस्तान को चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों से भी प्रोत्साहन मिला, जिसका उद्देश्य भारत को अलग-थलग करना था।

ताशकंद घोषणा (Tashkent Declaration)

भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सभी नियंत्रण वाले क्षेत्रों से पीछे हटने और युद्ध-पूर्व स्थितियों में लौटने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने युद्ध के कैदियों को भी वापस लौटाने और बल का प्रयोग न करने तथा शांतिपूर्ण साधनों से अपने मतभेदों को हल करने पर सहमति जताई।

हालाँकि, ताशकंद घोषणा-पत्र कश्मीर के मूल मुद्दे को हल करने में विफल रहा। इस युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि मलेशिया और सिंगापुर को छोड़कर कोई भी देश खुलकर भारत का समर्थन करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि सोवियत संघ ने भी, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताने के बाद, पाकिस्तान के मामले में कई अन्य देशों की तरह तटस्थता की नीति अपनाई।

इंदिरा गाँधी के अधीन विदेश नीति (Foreign Policy under Indira Gandhi)

लाल बहादुर शास्त्री के अचानक निधन के बाद, इंदिरा गाँधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने मुख्य रूप से गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया, लेकिन उनकी नीति आदर्शवादी की तुलना में अधिक यथार्थवादी थी। शास्त्री जी के विपरीत, इंदिरा गाँधी ने नेहरू की बेटी के रूप में अधिकांश देशों का दौरा किया था। इंदिरा गाँधी की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व में भारत की खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करना था। वैश्विक मामलों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण, उन्हें विश्व के महत्त्वपूर्ण नेताओं में से एक के रूप में मान्यता मिलने लगी थी।

> "केवल सह-अस्तित्व से ही अस्तित्व संभव है। हम अहस्तक्षेप और गैर-हस्तक्षेप को अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के आधारभूत नियम मानते हैं।"
>
> *(प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी, सातवें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण में, नई दिल्ली, 7 मार्च, 1983)*

बांग्लादेश संकट (Bangladesh Crisis)

वर्ष 1970 में पाकिस्तान में स्वतंत्र चुनाव हुए, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में बंगाल की अवामी पार्टी ने 98 प्रतिशत से अधिक सीटों पर सफलता प्राप्त की थी। इसका आशय था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय विधानसभा में पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन सेना ने अवामी पार्टी को सरकार बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया में, अवामी पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर दमन शुरू कर दिया, जिसके कारण लाखों लोग भारत की ओर पलायन कर गए।

इंदिरा गाँधी के नेतृत्व वाली सरकार ने धैर्य रखते हुए विश्व शक्तियों को पूर्वी पाकिस्तान में दमन की वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए सावधानीपूर्वक कदम उठाए, साथ ही शरणार्थियों के मुद्दे के कारण भारत पर पड़ने वाले बोझ से भी अवगत कराया। भारत ने बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक और भौतिक समर्थन प्रदान किया।

पाकिस्तान ने भारत पर इसे विभाजित करने के षड्यंत्र का आरोप लगाया। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से समर्थन प्राप्त हुआ। इस संकट का सामना करने के लिए भारत ने 20 वर्ष की भारत-सोवियत शांति, मैत्री और सहयोग संधि (Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Cooperation) पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में किसी भी देश के सैन्य ख़तरे के मामले में तत्काल आपसी परामर्श और उचित प्रभावी उपाय करने का प्रावधान किया गया था।

दस दिनों के भीतर, भारतीय सेना ने ढाका को तीन ओर से घेर लिया और लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश के स्वतंत्र देश बनते ही, भारत ने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की। बाद में, 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गाँधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे शांति की बहाली को औपचारिक रूप दिया गया।

शिमला घोषणा (Shimla Declaration - 1972)

युद्ध विराम के बाद, भारत पश्चिमी और कश्मीर मोर्चे से सेना की वापसी के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के लिए तैयार था। साथ ही, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी भारत को पश्चिमी मोर्चे पर उच्च स्तर की सैन्य उपस्थिति बनाए रखने के लिए मज़बूर करेगा, पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता करना आवश्यक था।

शिमला समझौते के परिणाम (Outcomes of Shimla Agreement)

- कुछ रणनीतिक बिंदुओं को छोड़कर, भारत ने युद्ध के दौरान नियंत्रित की गई पाकिस्तानी भूमि को लौटाने पर सहमति व्यक्त की।
- पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (LoC) का सम्मान करने तथा उसमें एकतरफा बदलाव न करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- दोनों देश अपने मुद्दों को बाह्य हस्तक्षेप के स्थान पर द्विपक्षीय ढंग से सुलझाने पर भी सहमत हुए।
- भारत ने पाकिस्तान-बांग्लादेश समझौते की शर्त पर युद्धबंदियों को पाकिस्तान को लौटाने पर सहमति व्यक्त की।

बांग्लादेश संकट के परिणामस्वरूप घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गाँधी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। युद्ध से भारत को कई सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए:

- भारत ने अपना खोया हुआ गौरव और आत्मसम्मान पुन: प्राप्त किया, जो उसने 1962 के युद्ध के दौरान खो दिया था।
- युद्ध के बाद, लगभग 10 मिलियन शरणार्थी अपने घरों को लौट गए। इस प्रकार, भारत के संसाधनों पर दबाव डालने वाली एक गंभीर शरणार्थी समस्या का समाधान हो गया।
- भारत दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भी उभरा।
- इस पूरे प्रकरण को सँभालने के तरीके तथा पाकिस्तान के साथ शांति प्रक्रिया शुरू करने के लिए शिमला समझौते के कारण विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा एक नई ऊँचाई पर पहुँच गई और उसके मनोबल में वृद्धि हुई।

चीन और पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों का पुनरुद्धार (Revival of Diplomatic Relationship with China and Pakistan)

वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के पश्चात्, चीन के साथ भारत के संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए थे। हालाँकि, वर्ष 1976 तक स्थिति बदल गई, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया में एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर चुका था। भारत ने वर्ष 1971 के युद्ध, वर्ष 1974 के परमाणु परीक्षण और वर्ष 1975 में सिक्किम के विलय में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। साथ ही, भारत वर्ष 1971 की संधि के बाद सोवियत संघ पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता था। चीन भी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में सोवियत प्रभाव को कम करना चाहता था।

उपर्युक्त विचारों के परिणामस्वरूप, भारत ने एक साहसिक निर्णय लेते हुए, चीन के साथ लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों को सामान्य करने के लिए एकतरफा रूप से राजनयिक संबंधों को बहाल करने की घोषणा की। चीन ने इस कदम का स्वागत किया और राजनयिक संबंधों की बहाली के साथ प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों की भी बहाली हुई।

इसी प्रकार, 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद से भारत-पाक संबंध भी तनावपूर्ण थे। लेकिन वर्ष 972 के शिमला समझौते ने अंतत: संबंधों को सामान्य बनाने और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। शांति प्रक्रिया की बहाली की अन्य दक्षिण एशियाई देशों ने भी बहुत सराहना की।

सोवियत संघ के साथ संबंध (Relationship with Soviet Union)

इंदिरा गाँधी वर्ष 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनीं। वर्ष 1970 तक, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया था और देश में अपनी स्थिति मज़बूत कर ली थी। इस दौरान भारत को चीन और पाकिस्तान से ख़तरा था, जबकि अमेरिका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। इस स्थिति ने भारत और सोवियत संघ के बीच संबंधों को और मज़बूत किया।

इंदिरा गाँधी द्वारा प्रिवी पर्स का उन्मूलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और समाज के समाजवादी स्वरूप की स्थापना के निर्णय ने सोवियत संघ को भी प्रभावित किया। 1970 के दशक तक, सोवियत संघ भारतीय वस्तुओं का दूसरा सबसे बड़ा ख़रीदार बन गया था, साथ ही उसने भारत को भारी उद्योग स्थापित करने में मदद की और अत्याधुनिक सैन्य उपकरण भी मुहैया कराए। सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर भी भारत के पक्ष का समर्थन किया।

भारत-सोवियत संधि (Indo&Soviet Treaty - 1971)

भारत और सोवियत संघ ने शांति, मैत्री और सहयोग की 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने वर्षों से दोनों देशों के बीच तेज़ी से विकसित हो रही मैत्री और सहयोग को औपचारिक रूप प्रदान किया और उनके आपसी संबंधों को एक नए और उच्च स्तर पर पहुँचा दिया।

जब भारत ने पोखरण (1974) में परमाणु परीक्षण किया, तो फ्रांस और सोवियत संघ को छोड़कर लगभग सभी परमाणु शक्तियों ने इसकी आलोचना की। फ्रांस और सोवियत संघ ने इस मुद्दे पर निरंतर चुप्पी बनाए रखी, जो एक प्रकार से भारत के रुख का समर्थन था।

दोनों देशों के बीच आपसी समझ के आधार पर संबंध जारी रहे, जिससे सोवियत संघ ने शिमला समझौते का स्वागत किया और लंबित मुद्दों को द्विपक्षीय रूप से हल करने की भारतीय पहल का समर्थन किया। सोवियत संघ ने हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के इंदिरा गाँधी के रुख का भी समर्थन किया। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में भी भारत-सोवियत संबंध बहुत महत्त्वपूर्ण थे।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध (Relationship with the USA)

इंदिरा गाँधी के नेतृत्व के पहले चरण के दौरान, चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के प्रयासों, बांग्लादेश संकट के दौरान पाकिस्तान का पक्ष लेने, सामान्य रूप से पाकिस्तान को हथियारों की बिक्री और

डिएगो गार्सिया (हिंद महासागर) के द्वीप में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे की स्थापना के कारण अमेरिका के साथ संबंध ख़राब हो गए थे। इंदिरा गाँधी ने हिंद महासागर को शीत युद्ध की रणनीति से मुक्त करने की बात कही, जो अमेरिकी नेतृत्व को पसंद नहीं आई। अमेरिका ने वर्ष 1974 में परमाणु परीक्षण करने के लिए भी भारत की आलोचना की।

डिएगो गार्सिया को लेकर मतभेद (Differences Over Diego Garcia)

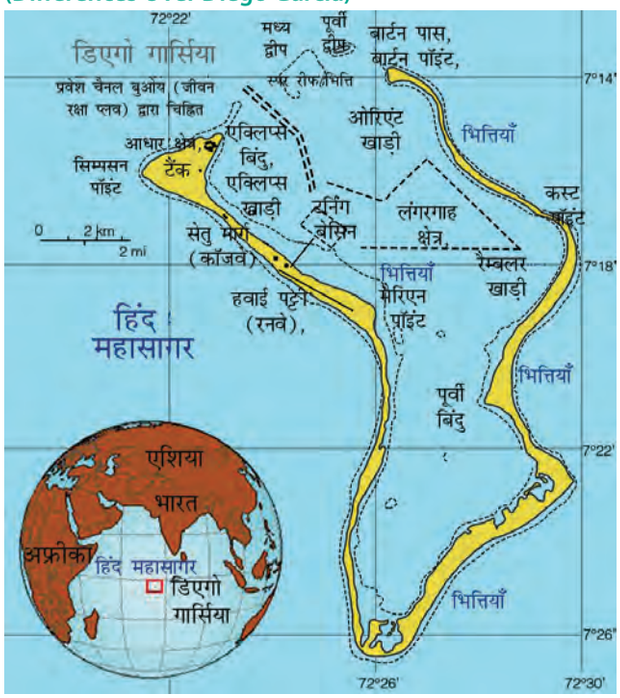

अमेरिका ने अपनी नौसैनिक शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से हिंद महासागर में एक रणनीतिक द्वीप डिएगो गार्सिया को एक मज़बूत नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित करने का निर्णय किया था। उसने एशिया में अपने हितों की रक्षा करने तथा एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती रूसी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए हिंद महासागर में इस नौसैनिक अड्डे का विकास किया। इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, भारत ने हिंद महासागर में महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता का कड़ा विरोध किया। इसके अलावा, भारत को लगा कि हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया को एक मज़बूत सैन्य अड्डे के रूप में विकसित करने से निश्चित रूप से न केवल महाशक्तियों के बीच, बल्कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भी तनाव बढ़ेगा।

इंदिरा गाँधी के नेतृत्व के दूसरे चरण के दौरान, अमेरिका ने भारत को तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ऋण और ईंधन प्राप्त करने में मदद की। दोनों देशों के बीच व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ा।

राजीव गाँधी का कार्यकाल (Rajiv Gandhi Years)

राजीव गाँधी ने नेहरू और इंदिरा गाँधी द्वारा निर्धारित विदेश नीति का अनुसरण किया, लेकिन कुछ आधारों पर उनसे भिन्नता भी रखी, इस प्रकार उन्होंने एक सीमा तक अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया।

उनकी नीति का उद्देश्य मानवता के बीच सौहार्द और सद्भावना कायम करना था। इसके लिए उन्होंने बेहतर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और परमाणु नि:शस्त्रीकरण का समर्थन किया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि राष्ट्रों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए नस्लीय सद्भाव एक पूर्व शर्त है। राजीव गाँधी ने एक सक्रिय विदेश नीति का पालन करना जारी रखा और विश्व समुदाय में भारत का स्थान सुनिश्चित किया।

उन्होंने दृढ़ता से कहा कि तेज़ी से बदलती विश्व व्यवस्था में, हमारे देश को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप लचीला बने रहना चाहिए और अतीत में नहीं उलझे रहना चाहिए। साथ ही, बुनियादी सिद्धांत और मौलिक नैतिक धारणाएँ मज़बूत होनी चाहिए। जनवरी 1985 में, उन्होंने निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की:

- विश्व शांति
- पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर सभी देशों के साथ मैत्री
- गुटनिरपेक्षता
- न्याय, पारस्परिक सहयोग, शांति और विकास पर आधारित नई विश्व आर्थिक व्यवस्था
- अन्य राज्यों की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान तथा राष्ट्रों की संप्रभु समानता के सिद्धांतों के प्रति सम्मान, उनके आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप
- दक्षिण एशिया में हमारे निकटतम पड़ोसियों के साथ गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करना
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व
- विश्व राजनीति के बदलते संदर्भ में निरंतरता और परिवर्तन, स्थिरता और गतिशीलता के दोहरे सिद्धांतों का पालन करना।

उनके नेतृत्व में, भारत ने सोवियत संघ से सहायता लेने के स्थान पर तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए पश्चिम की ओर रुख किया, जो उनके पूर्ववर्तियों की नीति से भिन्न नीति थी। इससे पश्चिम के साथ संबंधों में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

नि:शस्त्रीकरण के प्रयास (Disarmament Efforts)

राजीव गाँधी ने विशेष रूप से वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न मंचों पर परमाणु नि:शस्त्रीकरण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में भारत के रुख की घोषणा की, जब उन्होंने कहा "भारत परमाणु नि:शस्त्रीकरण के लिए तब से लड़ रहा है, जब इसकी कवायद भी शुरू नहीं हुई थी। हमें एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में कार्य

करना चाहिए। हमें इस प्रक्रिया में सभी परमाणु हथियार संपन्न देशों को शामिल करना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि परमाणु हथियार शक्तियाँ नए आयामों तक विस्तारित न हो जाएँ। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि बड़े पैमाने पर विनाश के अन्य हथियार या सर्जिकल हथियारों का विकास न हो। हमें निवारक सिद्धांत के स्थान पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत को अपनाना चाहिए।"

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता (Commitment to Non-Alignment Movement)

राजीव गाँधी ने वर्ष 1985 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जब उन्होंने कहा कि NAM भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक तार्किक विकास था, जिसने आधी सदी पहले विश्व के शेष उपनिवेशित हिस्सों को रास्ता दिखाया। उन्होंने बदलते विश्व में नई चुनौतियों, विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों, का सामना करने के लिए NAM में अधिक सामंजस्य प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करते हुए नस्लवाद और उपनिवेशवाद के हमलों का मुकाबला करना उनके द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे थे, जिन्हें NAM को संबोधित करना चाहिए।

राजीव गाँधी ने इस बात पर बल दिया कि पर्यावरण संरक्षण और विकास के मुद्दे एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इसके लिए उन्होंने ऊर्जा संरक्षण और वायुमंडलीय प्रदूषण से निपटने के लिए एक अद्वितीय मल्टी-बिलियन डॉलर के प्लैनेट प्रोटेक्शन फ़ंड (संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में) के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास किया।

राजीव गाँधी और हिंद महासागर (Rajiv Gandhi and Indian Ocean)

हिंद महासागर लंबे समय से विश्व राजनीति के केंद्र में रहा है और जब ब्रिटेन ने हिंद महासागर के द्वीप डिएगो गार्सिया को अमेरिका को सौंप दिया, तो इसकी गतिशीलता में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया, क्योंकि इसने इस क्षेत्र में शीत युद्ध के आधिपत्य के लिए द्वार खोल दिए थे। हिंद महासागर की केंद्रीयता को देखते हुए, यह स्पष्ट था कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर होगा।

राजीव गाँधी ने हिंद महासागर को शांति, स्थिरता और सहयोग के क्षेत्र में बदलने और इसे शीत युद्ध की राजनीति से अलग रखने के लिए ज़ोरदार आवाज़ उठाई। राजीव गाँधी ने बल देकर कहा कि हिंद महासागर परमाणु हथियारों से लैस विश्व नौसेनाओं के लिए एक खेल का मैदान बन गया है, और उन्होंने हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाने का समर्थन किया।

सार्क को मज़बूत करने के प्रयास (Efforts to Strengthen SAARC)

भारत ने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से अपने पड़ोसियों के साथ विवादास्पद द्विपक्षीय, राजनीतिक विवादों को दूर करने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में सार्क की क्षमता को पूर्ण रूप से समझा है। राजीव गाँधी ने इस बात पर बल दिया था कि सार्क का उद्देश्य सामूहिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा बहुपक्षवाद और विश्वव्यापी सहयोग की शक्तियों को मज़बूत करना होना चाहिए। उन्होंने सार्क को मज़बूत करने पर बल दिया और इसका उपयोग विशेष रूप से सात देशों के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी स्तरों पर चर्चाओं के लिए किया।

श्रीलंका में शांति मिशन (Peace Mission to Sri Lanka)

राजीव गाँधी की श्रीलंका नीति मज़बूत और सही थी, हालाँकि यह तर्क दिया जा सकता है कि कूटनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने शायद लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (NAM) की वास्तविक प्रकृति और लड़ाई क्षमता को कम करके आँका था। 29 जुलाई, 1987 को राजीव गाँधी और जे.आर. जयवर्धने ने कोलंबो में प्रसिद्ध भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत ने NAM की समस्या से लड़ने में मदद करने के लिए श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजने पर सहमति व्यक्त की थी। यह समझौता तब किया गया, था जब श्रीलंका के अपनी नृजातीय समस्या का सैन्य समाधान खोजने के प्रयास विफल हो गए थे। भारतीय शांति सेना (IPKF) को LTTE के साथ-साथ सिंहली राजनेताओं और भारत में विपक्षी नेताओं से भी कई मुद्दों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने बेहतरीन कार्य किया। बाद में, 24 मार्च, 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व में IPKF को वापस बुला लिया गया।

नरसिम्हा राव का कार्यकाल (Narsimha Rao Period)

उदारीकरण और विदेश नीति में परिवर्तन (Liberalisation and Changes in Foreign Policy)

वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति के तहत देश की विदेश नीति के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्रक में भी व्यापक परिवर्तन किए गए। हालाँकि भारत 1980 के दशक से ही कई भुगतान संतुलन संकटों का सामना कर रहा था, किंतु 1990 के दशक की परिस्थितियों ने भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोलने हेतु विवश कर दिया। इससे अत्यंत आवश्यक आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ। सरकार ने अपनी नीतियों में व्यापक परिवर्तन किए, भारतीय अर्थव्यवस्था को बाह्य विश्व के लिए खोल दिया गया तथा घरेलू स्तर पर भी अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए। इस प्रकार, सरकार ने नई आर्थिक नीति को अपनाया। इस नीति का उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना तथा सतत् रूप से उच्च संवृद्धि दर प्राप्त करना था।

द्विध्रुवीय विश्व का अंत और भारत की विदेश नीति (The End of the Bipolar World and India's Foreign Policy)

भारत के सोवियत संघ (USSR) के साथ घनिष्ठ आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संबंध थे। सोवियत संघ ने कश्मीर से लेकर बांग्लादेश संकट तक कई मुद्दों पर भारत का समर्थन किया

था। भारत-सोवियत संघ ने वर्ष 1972 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद भारत ने सोवियत संघ के साथ अनेक रक्षा समझौते किए और सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा शस्त्र निर्यातक बन गया।

यद्यपि शीत युद्ध के अंत ने भारत के लिए अमेरिका-सोवियत शक्ति प्रतिद्वंद्विता से उत्पन्न ख़तरे को समाप्त कर दिया था, किंतु इससे भारत के लिए कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो गई थीं। सोवियत संघ के विघटन के कारण भारत को शस्त्रों, कल-पुर्जों (स्पेयर पार्टस) की आपूर्ति, कश्मीर पर कूटनीतिक समर्थन तथा संयुक्त राष्ट्र के अंदर एवं बाहर विभिन्न राजनीतिक-रणनीतिक मुद्दों पर समर्थन तथा दक्षिण एशिया में अमेरिका के साथ शक्ति संतुलन हेतु समर्थन आदि मामलों में अनिश्चितता का सामना करना पड़ा।

सोवियत संघ के विघटन के पश्चात्, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा, जिससे दशकों से चल रहा शीत युद्ध और द्विध्रुवीय विश्व का अंत हो गया। इन बदलती परिस्थितियों में, भारत ने भी घटनाक्रम के अनुसार अपनी नीति में परिवर्तन किए।

इस संदर्भ में पहला बड़ा बदलाव भारतीय नीति का वैश्वीकरण की चुनौतियों के प्रति अनुकूल होना था, जो इसका प्राथमिक उद्देश्य भी बन गया था। इस प्रकार, भारत की विदेश नीति ने भारत को एक समाजवादी समाज से आधुनिक पूँजीवादी समाज के निर्माण की दिशा में रूपांतरित करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए, वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति की शुरुआत के साथ राष्ट्रीय आर्थिक नीति में परिवर्तन हुए। इसने बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विदेश नीति के मोर्चे पर कई विकल्प प्रदान किए।

बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ, भारत ने अपनी विदेश नीति में सैन्य और आर्थिक शक्ति को प्राथमिकता देना आरंभ कर दिया था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 2010 तक भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक बन गया था। इसका मुख्य कारण भारत की पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर संकट उत्पन्न करने वाले पड़ोसी देशों की मौजूदगी था। यह व्यावहारिकता भारत-अमेरिका संबंधों में बढ़ती निकटता में भी प्रतिबिंबित हुई, जो बाद में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के रूप में परिणत हुई। इसे 123 समझौते के रूप में भी जाना जाता है। आर्थिक उद्देश्यों के समावेश से भारत के कूटनीतिक पोर्टफ़ोलियो में विविधता आई है। इसके अतिरिक्त भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति ने वैश्विक मामलों में, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन और G-20 जैसे मंचों पर, वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए किए जा रहे इसके प्रयासों को सुदृढ़ किया है।

तेज़ी से बदलती घरेलू राजनीति ने भी भारत की विदेश नीति को प्रभावित किया। क्षेत्रीय दलों का महत्त्व बढ़ा तथा गठबंधन सरकारों के दौर ने विदेश नीति को अप्रत्याशित बना दिया। भारत द्वारा श्रीलंका से अपने शांति मिशन को अचानक वापस बुला लेना इसका एक मुख्य प्रमाण है। इसके अलावा, वर्ष 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान, भारतीय विदेश नीति में कई बार बदलाव किए गए, पहले विरोध किया गया, फिर समर्थन किया गया और फिर इराक की ओर जाने वाले अमेरिकी विमानों द्वारा भारतीय ईंधन भरने की सुविधाओं के उपयोग का भी विरोध किया गया।

भारत की बदलती विदेश नीति केवल 'महाशक्तियों' के साथ कूटनीति तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसने अपने पड़ोसी देशों के साथ भी वार्ता की। भारत ने अपने दो बड़े पड़ोसी देशों-पाकिस्तान और चीन के साथ राजनीतिक सुलह करने के लिए व्यापक प्रयास किए। 1990 के दशक के दौरान, भारत-पाकिस्तान संबंधों में अत्यधिक परिवर्तन देखे गए। दोनों देशों के संबंध सीमित पारंपरिक युद्ध से पूर्ण सैन्य टकराव में बदल गए। वर्ष 2004 से, ही संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए। इसमें कश्मीर विवाद को हल करने के लिए गंभीर वार्ता भी की गई। चीन के साथ, भारत ने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए सार्थक वार्ताओं की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया।

वर्ष 1991 के संसदीय चुनावों के बाद पी.वी. नरसिम्हा राव भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने। शीत युद्ध की समाप्ति के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव आए। वर्ष 1991 में द्विध्रुवीय विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुटबाज़ी की राजनीति का युग समाप्त हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद, अमेरिका ने एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र की अपनी स्थिति बरकरार रखी। भारत सहित सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस अचानक परिवर्तन को देखा था। इसलिए, भारतीय नेताओं को अब अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने और उसे नया रूप देने का कार्य सौंपा गया। नरसिम्हा राव ने निम्नलिखित के माध्यम से भारत का पुनर्गठन करने का प्रयास किया:

- **आर्थिक सुधार** (Economic Reforms): अर्थव्यवस्था को नियंत्रण मुक्त करना, राज्य नियंत्रण प्रणाली को शिथिल करना, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोलना और निजी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। सुधार की इस नीति का अमेरिका और अन्य औद्योगिक देशों ने स्वागत किया।
- **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** (International Relations): पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति का मुख्य ध्यान अमेरिका के साथ संबंध सुदृढ़ करने पर था। कई विशेषज्ञों का मानना था कि वर्ष 1991 के बाद भारतीय विदेश नीति न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बल्कि यूरोपीय संघ, रूस, चीन, जापान, इज़रायल, ब्राज़ील, दक्षिण अफ़्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक रूप से स्थिर देशों के साथ मज़बूत संबंध स्थापित करने पर आधारित थी।

वर्ष 1991 के बाद अमेरिका के साथ भारत के संबंध धीरे-धीरे बेहतर हुए। पी.वी. नरसिम्हा राव ने भी अपने "निकटतम" पड़ोसियों पाकिस्तान, चीन, नेपाल और श्रीलंका के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की। भारत ने नाटो (NATO)

के सदस्य देशों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाया और 1992 में इज़रायल के साथ सफलतापूर्वक औपचारिक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की।

देश की विदेश नीति के क्षेत्र में पी.वी. नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी उपलब्धि चीन के साथ शांति वार्ता पर हस्ताक्षर करना थी। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच दीर्घकाल से चले आ रहे सीमा विवाद को समाप्त करना था।

लुक ईस्ट नीति (Look East Policy)

पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा 1990 के दशक की शुरुआत में भारत की लुक ईस्ट नीति (LEP) का आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत के अलगाव को कम करना और क्षेत्रीय सहयोग की सुविधा का लाभ उठाने के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान/ASEAN) के साथ भारत की साझेदारी को बढ़ावा देना था। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ सार्थक सहयोग करने के भारत के प्रयास को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और वर्तमान में भारत एवं आसियान (ASEAN) जीवंत आर्थिक, रणनीतिक और राजनीतिक संबंध साझा करते हैं। इसमें वस्तु, सेवाओं और निवेश में मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर करना शामिल है। इसके अतिरिक्त समुद्री सुरक्षा, संपर्क (कनेक्टिविटी) आदि, साझा सहयोग के अन्य क्षेत्र हैं।

लुक ईस्ट नीति के कारण (Reasons for Look East Policy)

- **चीन का आर्थिक रूप से मुकाबला करना** (Economically Countering China): 1980 के दशक के दौरान चीन की व्यापार नीतियों के कारण उसका तेज़ी से विकास हुआ और दोनों देशों के बीच अनेक मोर्चों पर प्रतिस्पर्धा हुई। इसमें राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य क्षेत्र और सबसे महत्त्वपूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया के क्षेत्र में आर्थिक प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। इस प्रकार, भारत को आर्थिक रूप से एक नई आक्रामक नीति अपनाने की आवश्यकता थी।
- **उभरता हुआ मध्यम वर्ग** (Emerging Middle Class): भारत में शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों की एक बड़ी संख्या है, जो एक विशाल जनशक्ति समूह है, जिसका दोहन किया जाना शेष है। इस प्रकार, भारत ने कार्य के लिए चिंतित अपने कार्यबल और उत्पादों के निर्यात के लिए नए बाज़ारों की तलाश शुरू कर दी।
- **पश्चिम और मध्य एशिया से नियंत्रण** (Containment from West and Central Asia): इसके अलावा, भू-राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवाद के ख़तरे के कारण इन क्षेत्रों के साथ निवेश और व्यापार संबंध अनिश्चित रहे हैं। अत: भारत ने अधिक विश्वसनीय और स्थिर गंतव्यों की तलाश शुरू कर दी।

आई.के. गुजराल का कार्यकाल (I.K. Gujral Period)

भारतीय विदेश नीति के क्षेत्र में आई.के. गुजराल का विशेष स्थान है। गुजराल का मुख्य ध्यान भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर था। इस प्रकार, पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने नीतियों का एक समुच्चय तैयार किया, जिसे 'गुजराल सिद्धांत (Gujral Doctrine)' के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि गुजराल सिद्धांत ने भारत के अपने निकटतम पड़ोसियों, विशेषकर छोटे पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में अत्यधिक बदलाव किया।

गुजराल सिद्धांत भारत के निकटतम पड़ोसियों के साथ विदेशी संबंधों के संचालन का मार्गदर्शन करने के लिए पाँच सिद्धांतों का एक समुच्चय है, जिसे आई.के. गुजराल ने निर्धारित किया था। ये पाँच सिद्धांत इस विश्वास से उत्पन्न होते हैं कि भारत की प्रतिष्ठा और क्षमता का उसके पड़ोसियों के साथ संबंधों की गुणवत्ता से प्रत्यक्ष संबंध है। इस प्रकार, यह पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों को अधिकतम महत्त्व देता है।

ये सिद्धांत हैं:

- पड़ोसियों और अन्य देशों के साथ भारत को पारस्परिक आदान-प्रदान (Reciprocity) की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि सद्भावना और विश्वास के साथ वह सब कुछ देना चाहिए, जो वह दे सकता है।
- आपसी विश्वास उत्पन्न करने के लिए, क्षेत्र के किसी भी देश को अपनी भूमि का उपयोग किसी भी तरह से अन्य देशों के विरुद्ध नहीं करने देना चाहिए।
- क्षेत्र के देशों को एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
- प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए।
- तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना द्विपक्षीय मुद्दों का पारस्परिक समाधान।

अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल (A. B. Vajpayee Period)

अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1998 में गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की विदेश नीति में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विदेश नीति की पहलों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

परमाणु परीक्षण (1998) Nuclear Test (1998)

भारत ने परमाणु अप्रसार के उद्देश्य से की गई अंतर्राष्ट्रीय संधियों का विरोध किया है, क्योंकि ये केवल कुछ चयनित गैर-परमाणु शक्तियों पर लागू होती हैं और पाँच परमाणु हथियार शक्तियों के एकाधिकार को वैध बनाती हैं। इस प्रकार, भारत ने वर्ष 1995 में परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध किया और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर करने से भी इनकार कर दिया।

भारत ने मई 1998 में विभिन्न परमाणु परीक्षण किए, जिससे सैन्य उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की उसकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान ने भी जल्द ही इसका अनुसरण किया, जिससे परमाणु विनिमय के लिए क्षेत्र की सुभेद्यता बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उपमहाद्वीप में परमाणु परीक्षणों की अत्यधिक आलोचना कर रहा था और भारत एवं पाकिस्तान दोनों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिन्हें बाद में हटा दिया गया।

भारत का 'विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिवारण सिद्धांत (Doctrine of Credible Minimum Nuclear Deterrence)' 'पहले उपयोग नहीं करने' की नीति पर आधारित है। यह वैश्विक, सत्यापन योग्य और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु नि:शस्त्रीकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है, जिससे परमाणु हथियार मुक्त विश्व का निर्माण होगा।

परमाणु परीक्षण पर वैश्विक प्रतिक्रिया (Global Response to Nuclear Test)

- भारत के परमाणु परीक्षण की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कड़ी आलोचना की गई।
- परमाणु परीक्षणों से भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न हो गई थी।
- अमेरिका और जापान सहित कई देशों ने परीक्षण करने तथा NPT और CTBT के खिलाफ जाने के लिए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे।
- इन परीक्षणों ने वैश्विक शक्तियों के साथ सुधरते संबंधों में पुन: तनाव उत्पन्न कर दिया था।

भारत की प्रतिक्रिया (India's Response)

भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि परमाणु परीक्षण का लक्ष्य इसे किसी देश के विरुद्ध उपयोग करना नहीं, बल्कि अपने हितों की रक्षा करना था। भारत ने हमेशा परमाणु अप्रसार संधियों (NPT और CTBT) की भेदभावपूर्ण प्रकृति के खिलाफ अपना विरोध जताया है।

भारत-पाकिस्तान (India-Pakistan)

- **बस कूटनीति** (Bus Diplomacy): वर्ष 1998 के परमाणु परीक्षणों ने भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव को और बढ़ा दिया था। अत: भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए नई दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू करने का एक अभिनव विचार किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और मित्रता के बंधन को मज़बूत करना था।

  बस कूटनीति दोनों देशों के बीच उथल-पुथल भरे रिश्तों के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। बस कूटनीति के तहत वाजपेयी स्वयं लाहौर गए और 21 फरवरी, 1999 को लाहौर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
- **लाहौर घोषणा-पत्र** (Lahore Declaration): भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1999 में लाहौर घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा-पत्र में सहयोग और सह-अस्तित्व के सिद्धांत पर कार्य करने तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों को कम करने का प्रण लिया गया था।

लाहौर घोषणा के प्रस्ताव
(Proposals of Lahore Declaration)

- इसमें दोनों देशों के सुरक्षात्मक वातावरण में परमाणु आयाम को मान्यता दी गई।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता स्वीकार की गई।
- यह शिमला समझौते को अक्षरश: लागू करने के लिए दोनों देशों के दृढ़ संकल्प को दोहराता है।
- इसमें सार्वभौमिक परमाणु नि:शस्त्रीकरण और अप्रसार के उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

- इसमें सुरक्षात्मक वातावरण में सुधार के लिए पारस्परिक रूप से सहमत विश्वास-निर्माण उपायों के महत्त्व को स्वीकार किया गया।
- इसमें माना गया कि शांति और सुरक्षा का वातावरण दोनों पक्षों के सर्वोच्च राष्ट्रीय हित में है और इस उद्देश्य के लिए जम्मू और कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों का समाधान आवश्यक है।

हालाँकि, यह घोषणा अपेक्षित दिशा में आगे नहीं बढ़ी, स्थिति तब और बिगड़ गई जब मई 1999 के मध्य में पाकिस्तान से आए घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा पर रणनीतिक स्थलों, विशेषकर कश्मीर के कारगिल सेक्टर, पर कब्ज़ा कर लिया।

कारगिल संघर्ष (Kargil Conflict)

कारगिल में पाकिस्तान की सशस्त्र घुसपैठ के बाद, भारत ने घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए 'ऑपरेशन विजय' शुरू किया। भारत ने अमेरिका और उसके प्रमुख वार्ताकारों को घटनाक्रम और घुसपैठ की प्रकृति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कारगिल में पाकिस्तान की सशस्त्र घुसपैठ के बारे में स्पष्ट रुख अपनाया और घुसपैठियों को वापस बुलाने का आह्वान किया। अमेरिका ने भारत द्वारा संयम और ज़िम्मेदारी से ऑपरेशन को संचालित करने की सराहना भी की। भारत के रुख को अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी मीडिया से समर्थन मिला।

इसी तरह, दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद, भारत ने दबावपूर्ण कूटनीति की रणनीति अपनाई, हालाँकि इसके परिणाम मिश्रित रहे। यह रेखांकित करना महत्त्वपूर्ण है कि इन दोनों संकटों में से कोई भी संकट दीर्घकालिक शत्रुओं के बीच पूर्ण रूप से युद्ध में परिणत नहीं हुआ।

वाजपेयी और भारत-अमेरिका संबंध (Vajpayee and India-US Relations)

भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर मतभेदों और CTBT पर हस्ताक्षर करने की अनिच्छा के बावजूद, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने दोनों देशों के बीच भविष्य के गतिशील संबंधों को बनाने के उद्देश्य से मार्च 2000 में भारत की पाँच दिवसीय यात्रा की। इसी तरह बदले में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने सितंबर 2000 में अमेरिका की यात्रा की। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते आर्थिक संपर्क पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में एक प्रमुख प्रेरक शक्ति बन गए थे।

मनमोहन सिंह का कार्यकाल (Manmohan Singh Period)

नेहरू द्वारा निर्धारित भारत की विदेश नीति के व्यापक ढाँचे को बाद के नेताओं ने सर्वसम्मति से अपनाया, लेकिन देश की परिस्थितियों और ज़रूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव आना शुरू हो गया। जब मनमोहन सिंह सत्ता में आए, तब तक भारत की विदेश नीति नेहरू युग की तुलना में काफ़ी बदल चुकी थी। कूटनीति ज़्यादा सौम्य, मैत्रीपूर्ण और अधिक मिलनसार हो गई थी।

रूस के साथ संबंध (Relationship with Russia)

रूस ने भारत के महत्त्व को समझा और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। यह भावना वर्ष 2007 में रूस की यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह के गर्मजोशी से स्वागत में परिलक्षित हुई।

अपने संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित करने पर सहमति जताई। इस दौरान उनका मुख्य फ़ोकस सैन्य क्षेत्र पर था, जहाँ कई समझौते संपन्न हुए। इनमें सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइलों का विकास और सैन्य सहयोग पर 10 वर्षीय समझौते को वर्ष 2010 से आगे बढ़ाना शामिल है।

रूस ने भारत की परमाणु नीति को मान्यता दी और तमिलनाडु के कुडनकुलम में अन्य चार असैन्य परमाणु रिऐक्टर बनाने का वादा किया। आर्थिक संपर्क को बढ़ाने के भी प्रयास किए गए, ये प्रयास पारंपरिक रुपया-रूबल व्यवस्था से बढ़कर थे। इस प्रकार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत-रूस संबंध एक नई ऊँचाई पर पहुँच गए।

अमेरिका के साथ संबंध (Relationship with USA)

मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका एक-दूसरे के निकट आए। इसे वास्तव में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक बड़ी छलाँग कहा जा सकता है।

दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने में निम्नलिखित कारकों का योगदान रहा है:

- सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने तत्कालीन सोवियत संघ के साथ अपने विशेषाधिकार प्राप्त संबंधों को समाप्त कर दिया था।
- उभरते हुए शक्तिशाली चीन को प्रतिसंतुलित करने की आवश्यकता थी।
- अमेरिकी नेतृत्व के बीच भी यह व्यापक धारणा थी कि भारत अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए तैयार है।
- विनियमन-मुक्त एवं उदारीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था ने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विस्तार के लिए आकर्षक स्रोत के रूप में कार्य किया।
- भारत से बाहर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में भी आतंकवाद उन्मुख इस्लामिक कट्टरवाद का अत्यधिक विस्तार होता जा रहा था, जिसका प्रमुख लक्ष्य भारत को माना जा रहा था। इसके लिए भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता थी।

इस पृष्ठभूमि में, भारत और अमेरिका ने ऐतिहासिक भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल को शुरू करने में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के तीन साझा उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- 30 से अधिक वर्षों से दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों में बाधा उत्पन्न करने वाले मूल मतभेदों को दूर करना,
- पर्यावरण-अनुकूल तरीके से भारत की आर्थिक संवृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोग करना, और
- वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था को मज़बूत करना।

इस समझौते को अमेरिका-भारत संबंधों में मील का पत्थर माना जाता है और इसने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक नया पहलू जोड़ा है। इस समझौते ने भारत के साथ परमाणु व्यापार पर तीन दशक से चली आ रही अमेरिकी बाधा को हटा दिया। इसने भारत के असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को अमेरिकी सहायता प्रदान की और ऊर्जा एवं उपग्रह प्रौद्योगिकी में अमेरिका-भारत सहयोग का विस्तार किया।

विश्वसनीय परमाणु प्रतिवारण की विशेषताएँ (Features of Credible Nuclear Deterrence)

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी समूह, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संघ (IAEA) के निरीक्षकों को अपने असैन्य परमाणु कार्यक्रम तक पहुँच प्रदान की है तथा अपने 22 विद्युत रिऐक्टरों में से 14 को स्थायी रूप से IAEA सुरक्षा मानकों के अंतर्गत रखा है।
- समझौते के तहत भारत ने अपने परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा करने तथा उसे गलत हाथों में पड़ने से बचाने की भी प्रतिबद्धता जताई है।
- अमेरिकी कंपनियों को भारत में परमाणु रिऐक्टर बनाने और उसके नागरिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए परमाणु ईंधन उपलब्ध कराने की अनुमति दी जाएगी। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा भारत के ऊपर से प्रतिबंध हटाने की मंज़ूरी से अन्य देशों के लिए भारत को परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी की बिक्री करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
- भारत अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी ख़रीदने के लिए पात्र हो जाएगा, जिसमें ऐसी सामग्री और उपकरण शामिल होंगे, जिनका उपयोग यूरेनियम संवर्धन या प्लूटोनियम के पुनर्प्रसंस्करण के लिए किया जा सकता है।
- भारत ने एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो IAEA को इसके सिविल प्रतिष्ठानों में अधिक हस्तक्षेपपूर्ण निरीक्षण की अनुमति देगा।
- भारत ने परमाणु हथियार परीक्षण पर रोक जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की है।

वर्ष 2008 में, IAEA के बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स ने भारत के सुरक्षा समझौते को मंज़ूरी दे दी, जिससे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत को शामिल करने के विचार का मार्ग प्रशस्त हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के विस्तारित शांतिपूर्ण परमाणु क्षेत्र के साथ व्यापार की अनुमति देने के लिए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत को छूट दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पाकिस्तान के साथ संबंध (Relationship with Pakistan)

इस दौरान भारत और पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे या व्यापक शांति समझौते पर एकमत नहीं हो पाए। वर्ष 2008 के मुंबई हमलों और उसके बाद इस बात के सबूत मिलने के बाद कि हमलावरों को पाकिस्तानी सेना एवं खुफिया प्रतिष्ठान का समर्थन प्राप्त था, दोनों देशों के बीच संबंध और भी ख़राब हो गए।

बाद में, दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए, सितंबर 2012 में एक उदार वीज़ा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत, दोनों देशों के 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आगमन पर वीज़ा दिया जा सकता है और दोनों देशों के व्यवसायी दोनों देशों के बीच अधिक स्वतंत्रतापूर्वक यात्रा कर सकते हैं।

चीन के साथ संबंध (Relationship with China)

इस अवधि के दौरान चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए। वर्ष 2005 में तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने भारत का दौरा किया। इस दौरान चीन ने आधिकारिक तौर पर सिक्किम को "भारत के अविभाज्य अंग" के रूप में मान्यता दी, जिससे सिक्किम अब भारत-चीन संबंधों में कोई मुद्दा नहीं रह गया।

वर्ष 2013 में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था, क्योंकि लद्दाख एवं अक्साई चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच तीन सप्ताह तक गतिरोध रहा था। यह तनाव तब कम हुआ, जब भारत ने बंकरों को ध्वस्त करने और चीन ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति जताई।

मनमोहन सिद्धांत (Manmohan Doctrine)

मनमोहन सिंह की विदेश नीति के सिद्धांतों को मनमोहन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया है:

- भारत की विकास संबंधी प्राथमिकताएँ विश्व के साथ हमारे संबंधों को दिशा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के साथ और अधिक एकीकृत करने के पक्षधर थे, जिससे भारत को

लाभ होगा और भारतीय लोग अपनी रचनात्मक क्षमता को पहचान सकेंगे।

- हम सभी प्रमुख शक्तियों के साथ स्थिर, दीर्घकालिक और परस्पर लाभकारी संबंध स्थापित करना चाहते हैं। हम सभी देशों के लिए लाभकारी वैश्विक, आर्थिक और सुरक्षात्मक वातावरण के निर्माण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं।
- हम मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के साझा भविष्य के लिए क्षेत्रीय सहयोग और कनेक्टिविटी की अत्यधिक आवश्यकता है। इस दिशा में, हमें क्षेत्रीय संस्थागत क्षमता और सामर्थ्य को मज़बूत करना चाहिए और कनेक्टिविटी में निवेश करना चाहिए।
- हमारी विदेश नीति केवल हमारे हितों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उन मूल्यों से भी निर्धारित होती है, जो हमारे लोगों के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं।

नरेंद्र मोदी के अंतर्गत विदेश नीति
(Foreign Policy under Narendra Modi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साहसिक कदम उठाते हुए अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों के अपने समकक्षों को आमंत्रित किया। यह "पड़ोस प्रथम (नेबरहुड फ़र्स्ट)" विदेश नीति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ऊर्जावान, अतीत की धारणाओं को तोड़ने वाली और जोख़िम उठाने की प्रवृत्ति से प्रेरित रही है।

उनकी नीतियों का उद्देश्य विदेशी पूँजी एवं तकनीक को आकर्षित करना और भारतीय उत्पादों के लिए विदेशी बाज़ारों की तलाश करना है। साथ ही यह क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और समृद्धि के घनिष्ठ संबंध की ओर भी उन्मुख हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति में एक स्पष्ट परिवर्तन और असाधारण गतिशीलता दिखाई देती है। वास्तव में, भारत 'मोदी सिद्धांत' के उदय का गवाह बन रहा है। 4 डी-डेमोक्रेसी (लोकतंत्र), डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी), डिमांड (माँग) और डायस्पोरा (प्रवासी) ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति में एक ज़बरदस्त गुणक के रूप में काम किया है।

विशेषताएँ (Features):

- अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूमिका को एक 'संतुलनकारी शक्ति' के बजाय 'एक अग्रणी शक्ति' के रूप में परिवर्तित करना।
- कूटनीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने पर केंद्रित होना चाहिए।
- वर्तमान विश्व में रक्षा-क्षमता और आर्थिक शक्ति महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ ही भारत को अपनी 'सॉफ़्ट पावर' का भी पर्याप्त उपयोग करना चाहिए।
- भारतीय प्रवासी एक संपत्ति है, जो केवल धन प्रेषण तक सीमित नहीं है। इसलिए भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को सावधानीपूर्वक अभिलक्षित किया जाना चाहिए और विदेशों में संकटग्रस्त भारतीयों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने एक नया मार्ग अपनाया है और विचारों में व्यापक बदलाव दिखाई दे रहा है।

मोदी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएँ
(Key Features of the Modi Doctrine)

भारत प्रथम (India First)

'भारत प्रथम' मोदी सिद्धांत की बुनियादी विशेषता है। भारत के विकल्प और कार्यवाहियाँ उसकी राष्ट्रीय शक्ति की क्षमताओं पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, भारत की रणनीतिक मंशा मुख्य रूप से यथार्थवाद, सह-अस्तित्व, सहयोग और साझेदारी द्वारा निर्धारित होती हैं। मोदी की विदेश नीति 'वसुधैव कुटुम्बकम' (पूरा विश्व हमारा परिवार है) के बुनियादी मूल्य द्वारा निर्देशित हैं।

भारत के विकास पर केंद्रित, मोदी की विदेश नीति 'सभी भारतीयों की सुरक्षा और समृद्धि के साथ भारत में सुधार और परिवर्तन के निरंतर अभियान द्वारा निर्देशित है।' 17 जनवरी, 2017 को दिल्ली में दूसरे रायसीना डायलॉग के उद्घाटन संबोधन में, मोदी ने इस बात पर बल दिया कि भारत का आर्थिक और राजनीतिक उदय "क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महत्त्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। यह शांति के लिए एक शक्ति, स्थिरता के लिए एक कारक, तथा क्षेत्रीय और वैश्विक समृद्धि का इंजन है।"

पड़ोस प्रथम नीति (Neighbourhood First Policy)

मोदी सिद्धांत की दूसरी महत्त्वपूर्ण विशेषता एक दृढ़ 'पड़ोस प्रथम' दृष्टिकोण है। एक 'समृद्ध और एकीकृत पड़ोस' मोदी का सपना है। इसलिए, मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के साथ मज़बूत संबंध बनाने के लिए भारत की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से इंगित किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रित करके एक सकारात्मक शुरुआत की, जो उनकी 'पड़ोस प्रथम' नीति का प्रतीक है। इसके पश्चात्, उन्होंने अपने पहले 19 महीनों के कार्यकाल में मालदीव को छोड़कर सभी सार्क देशों का दौरा किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। आज भारत के पड़ोसियों के साथ जुड़ाव में अधिक संपर्क, मज़बूत सहयोग और व्यापक संवाद जैसे विषय प्रमुख हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पड़ोसी देशों ने भी इस पहल पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।

सांस्कृतिक जुड़ाव और सॉफ्ट पावर को मज़बूत करना
(Strengthening Cultural Connect and Soft Power)

भारतीय मूल्य, संस्कृति और परंपरा या सभ्यता संबंधी जुड़ाव को बढ़ावा देना मोदी सिद्धांत की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जापान, चीन, मंगोलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि देशों के सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया गया। यहाँ भारत

और इन देशों के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंध आज भी दिखाई देते हैं, जो वास्तव में उल्लेखनीय है। उन्होंने साझा मूल्यों, परंपराओं और विरासत पर व्यापक रूप से चर्चा की है और इस तरह इन प्राचीन संबंधों को मज़बूत किया गया है।

भारत की सॉफ़्ट पावर कूटनीति का एक दुर्लभ उदाहरण तब देखने को मिला, जब संयुक्त राष्ट्र के साथ-साथ पूरे विश्व ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या सोशल मीडिया जैसी मोदी की पहल सॉफ़्ट पावर संवर्धन के अच्छे उदाहरण हैं।

भारतीय प्रवासी (Indian Diaspora)

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भारतीय प्रवासियों के साथ संबंधों को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से समृद्ध किया है। इसमें नियमों को सरल बनाना, उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान करना और सरकार के समग्र विकास एजेंडे से उन्हें जोड़ना शामिल है।

प्रवासी समुदाय के प्रति भारतीय सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण ने अनिवासी भारतीयों (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) के समुदाय को पुनः सक्रिय किया है। इससे उनके अपने मूल देश के साथ संबंध मज़बूत हुए हैं और उनके निवास देश में उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।

यह सार्वजनिक सभाओं और सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क जैसे विभिन्न माध्यमों से विदेशों में भारतीय समुदाय के साथ मोदी द्वारा बातचीत में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस तरह की केंद्रित भागीदारी व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विशेष रूप से राजनीतिक समर्थन जुटाने में सहायक हो सकती है।

कई अवसरों पर प्रवासी समुदाय ने सहायता के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। इन्हें त्वरित एवं प्रत्यक्ष संचार के माध्यम से सरकार द्वारा समय पर सहायता उपलब्ध कराई गई है।

मोदी का 'सबका साथ, सबका विकास' का दृष्टिकोण 'पूरी दुनिया के लिए एक विश्वास है। यह विभिन्न स्तरों, कई विषयों और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकट होता है।'

अमेरिका के साथ निकटता (Closeness with USA)

सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का दौरा किया और जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में नई दिल्ली आए। भारत-अमेरिका संबंधों में हुई प्रगति कुछ इस प्रकार हैं:

- **असैन्य परमाणु समझौता** (Civil Nuclear Agreement): अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, असैन्य परमाणु समझौते पर गतिरोध एजेंडा का मुख्य बिंदु था। इस समझौते को 123 समझौता भी कहा जाता है, दुर्घटना की स्थिति में मुआवज़े के लिए भारत के परमाणु दायित्व कानून तथा अमेरिका द्वारा भारत को आपूर्ति किए जाने वाले परमाणु ईंधन और अन्य सामग्रियों को ट्रैक करने की माँग पर दोनों देशों के बीच मतभेदों के कारण यह वार्ता रुकी हुई थी। भारत ने अपने परमाणु संयंत्र तक पहुँच की इस माँग को अनावश्यक हस्तक्षेप कहा। यह मतभेद भारतीय दायित्व कानून में संशोधनों और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपनी कार्यकारी शक्तियों के उपयोग के माध्यम से 'निगरानी' शर्त को हटाने के बाद सुलझा लिया गया।
- **रक्षा सहयोग** (Defence Cooperation): वर्ष 2014 में मोदी की यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग को अगले दशक तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। परिणामस्वरूप वर्ष 2015 में 'न्यू फ़्रेमवर्क फ़ॉर डिफेंस कोऑपरेशन' को औपचारिक रूप से नवीनीकृत किया गया।

भारत ने अगस्त 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (LEMOA), सितंबर 2018 में कम्युनिकेशंस कम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA) और वर्ष 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) पर हस्ताक्षर किए। LEMOA, COMCASA और BECA तीन ऐसे बुनियादी समझौते हैं, जिन्हें अमेरिका अपने निकट सहयोगियों और साझेदारों के साथ हस्ताक्षर करता है ताकि सेनाओं के बीच अंतर-संचालन (Interoperability) और उन्नत तकनीक की बिक्री को सक्षम बनाया जा सके।

लुक ईस्ट से ऐक्ट ईस्ट (Look East to Act East)

नरसिंहा राव सरकार द्वारा शुरू की गई और मनमोहन सिंह सरकार तक जारी रखी गई "लुक ईस्ट नीति" को प्रधानमंत्री मोदी ने 'ऐक्ट ईस्ट' के रूप में अपग्रेड किया, जो अधिक स्पष्ट इरादे का संकेत देती हैं। एशिया की व्यापक रणनीतिक संदर्भ के अनुसार, भारत की 'ऐक्ट ईस्ट' नीति के तीन अलग-अलग संस्थागत, वाणिज्यिक और सुरक्षा-संबंधी पहलू हैं।

संस्थागत स्तर पर, आसियान (ASEAN), बिम्सटेक (BIMSTEC) और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने भारत को एशिया के बहुपक्षीय नेटवर्क के साथ एकीकृत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह में सभी 10 आसियान नेताओं को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। कनेक्टिविटी के मामले में, भारत ने मणिपुर के मोरेह से 3,200 किमी लंबे भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग के कार्य को त्वरित किया है, जो आसियान को भारत के करीब लाने का एक महत्त्वपूर्ण मार्ग है। मोदी के नेतृत्व में, भारत अब क्षेत्रीय जुड़ाव में टोक्यो और वाशिंगटन की ओर झुकाव के मामले में चीन की संवेदनशीलताओं को लेकर उतना संकोची नहीं है।

कूटनीति और विकास को जोड़ना (Bridging Diplomacy and Development)

मोदी की विदेश नीति मुख्य रूप से भारत की विकासात्मक आवश्यकताओं द्वारा संचालित होती है। यह लगातार सुधार और

परिवर्तन के लिए प्रेरित करती है ताकि सभी नागरिकों की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। यह दृष्टिकोण भारत की व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, और 'मेक इन इंडिया' पहल से जुड़ी चिंताओं पर आधारित है। इसका मुख्य ध्यान विश्वभर के निवेशकों को आकर्षित करने पर रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारत को एक मज़बूत निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2017 के वित्तीय वर्ष में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 62 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जबकि वैश्विक FDI प्रवाह में गिरावट आई थी।

भारत की विदेश नीति कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इसमें चीन के साथ संबंधों को प्रबंधित करना, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य संतुलन बनाए रखना, आतंकवाद से लड़ना, ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा, अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को आकार देना और हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय हितों की सुरक्षा करना शामिल हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को संवाद और संचार में संलग्न रहना, विश्वास और आत्मविश्वास का निर्माण करना, आर्थिक संबंधों को मज़बूत करना, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, विकास हेतु सहायता प्रदान करना एवं साइबर सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में जागरूकता को बढ़ाना होगा। भारत को क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।

1.4 भारत की विभिन्न कूटनीतिक विशेषताएँ (India's Different Diplomatic Attributes)

सांस्कृतिक कूटनीति (Cultural Diplomacy)

सांस्कृतिक कूटनीति विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण रणनीति है। यह आधिकारिक पहलों और जनसंपर्क के माध्यम से अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करती है। सरल शब्दों में, सांस्कृतिक कूटनीति का अर्थ है किसी देश की संस्कृति का उपयोग उसकी विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए करना है। यह इस विचार पर आधारित है कि अच्छे संबंध, समझ और सम्मान की उर्वर भूमि पर विकसित हो सकते हैं।

महत्त्व (Significance)

सांस्कृतिक कूटनीति से एक देश के मूल्य और छवि को अन्य देशों के बीच बढ़ावा मिलता है। साथ ही, यह अन्य देशों और उनके लोगों के मूल्यों, संस्कृति और छवि को समझने में मदद करती है।

यह किसी सरकार के लिए अन्य देशों के साथ सम्मान और समझ में वृद्धि करने का सर्वोत्तम तरीका है।

सांस्कृतिक कूटनीति विभिन्न देशों के लोगों के बीच मज़बूत संबंध स्थापित कर सकती है, क्योंकि यह लोगों के बीच संवाद का एक मंच प्रस्तुत करती है, जिससे "विश्वास की नींव" तैयार होती है।

नीति-निर्माता इसके आधार पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य समझौते कर सकते हैं। इस कूटनीति से विभिन्न समुदायों के बीच जातीय संघर्षों को कम करने और एक-दूसरे की संस्कृति के बारे में समझ विकसित करने में मदद मिलती है। सांस्कृतिक कूटनीति सिर्फ कूटनीति करने वाले देश के हितों को ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के हितों को भी आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।

सांस्कृतिक कूटनीति एक व्यापक अवधारणा है। इसमें शैक्षिक छात्रवृत्तियाँ, देश-विदेश में विद्वानों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और कलाकारों की यात्राएँ, सांस्कृतिक समूहों के प्रदर्शन, सेमिनार और सम्मेलन आदि शामिल हैं।

भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर (India's Cultural Diplomacy and Soft Power)

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत ने सांस्कृतिक कूटनीति के महत्त्व को पहचाना है। विदेश मंत्रालय ने भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य किया है, जिसके परिणामस्वरूप भारत ने विभिन्न देशों के साथ 126 द्विपक्षीय सांस्कृतिक समझौते किए हैं और वर्तमान में अन्य देशों के साथ 58 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को लागू कर रहा है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत ने वर्ष 1950 में एक नोडल निकाय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् (ICCR) की स्थापना की थी। यह निकाय सांस्कृतिक केंद्रों, भारत के त्योहारों, भारतीय अध्ययन पीठों आदि के रूप में भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाता है। वर्तमान में 35 देशों में ICCR के सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजीव गाँधी ने भी विश्व भर में भारतीय त्योहारों को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा दिया था।

1990 के दशक से ही भारतीय संस्कृति विश्व भर में काफ़ी लोकप्रिय रही है, जिसमें भारतीय व्यंजन, योग, बॉलीवुड और समकालीन कला की स्वीकृति शामिल है। साथ ही, प्रवासी भारतीयों की आर्थिक सफलता ने विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया है।

इसे ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार वर्ष 2003 में शुरू किए गए प्रवासी भारतीय दिवस सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से भारतीय प्रवासियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके अलावा, विभिन्न देशों के साथ समय-समय पर हस्ताक्षरित सांस्कृतिक समझौतों के माध्यम से, भारत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और कई अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा दे रहा है। एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम 'भारत को जानो कार्यक्रम' (Know India Program) एक तीन सप्ताह का ओरिएंटेशन कार्यक्रम है, जो प्रवासी युवाओं पर केंद्रित है, जिससे

उन्हें भारत के विभिन्न पहलुओं और विभिन्न क्षेत्रों में देश द्वारा की गई प्रगति से अवगत कराया जाता है।

वर्तमान परिदृश्य (Present Scenario)

हाल ही के समय में सांस्कृतिक पहलुओं को बहुत अधिक महत्त्व दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार के अंतर्गत "सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध" भारतीय विदेश नीति में सॉफ़्ट पावर का एक महत्त्वपूर्ण घटक बन गया है।

भारत ने 4 मई, 2015 को भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस का आयोजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था, जो बौद्ध कैलेंडर का सबसे महत्त्वपूर्ण दिन है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। भारत की प्राचीन संस्कृति से गहराई से संबंधित योग, विदेशी लोगों के बीच लोकप्रियता और वैधता प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार आयुर्वेद को भी चीन की पारंपरिक चिकित्सा के समकक्ष स्थापित करने पर बल दिया जा रहा है। भारत की धार्मिक एवं दार्शनिक परंपराएँ, विशेष रूप से योग, देश की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

इसके अलावा, बॉलीवुड ने भी भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे इस उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापक स्वीकृति मिली है।

खेल कूटनीति (Sports Diplomacy)

खेल कूटनीति उस प्रक्रिया का वर्णन करती है, जिसके तहत खेलों का उपयोग कूटनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को प्रभावित करने के साधन के रूप में किया जाता है। यह सांस्कृतिक मतभेदों को दूर कर लोगों को एकजुट करने में सहायक होती है।

सामान्य तौर पर, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंध, राजनीतिक संबंधों का अनुसरण करते हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचों का आयोजन होता है, तो दोनों पक्षों में जोश चरम पर होता है। भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1952 से एक-दूसरे के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया, जब पाकिस्तान ने पहली बार भारत का दौरा किया था। हालाँकि, वर्ष 1965 और 1971 के युद्धों और सीमा संघर्षों के कारण दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंध ख़राब होने के परिणामस्वरूप क्रिकेट संबंधों को भी झटका लगा।

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ज़िया उल-हक़ ने अपने 'क्रिकेट फॉर पीस इनिशिएटिव' के तहत फरवरी 1987 में दोनों देशों के बीच एक टेस्ट मैच देखने के लिए भारत का दौरा करके क्रिकेट कूटनीति की शुरुआत की थी। इस पहल ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को फिर से बहाल करने में मदद की। किंतु वर्ष 1989 के कश्मीर संकट की पृष्ठभूमि में राजनीतिक संबंध फिर से बिगड़ गए, जिससे क्रिकेट कूटनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ दोनों देशों के क्रिकेट संबंध एक बार फिर से बिगड़ गए।

वर्ष 1997 में भारत के पाकिस्तान दौरे के साथ क्रिकेट संबंधों की फिर से शुरुआत हुई, किंतु अगले ही वर्ष दोनों देशों के परमाणु परीक्षण के कारण ये संबंध फिर से ख़राब हो गए। वर्ष 1999 में पाकिस्तान का भारत दौरा क्रिकेट संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम था, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की उम्मीदें बढ़ीं।

वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध और पाकिस्तान-आधारित 'इस्लामी कट्टरपंथियों' द्वारा इंडियन एयरलाइंस के विमान अपहरण के बाद, भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध और अधिक बिगड़ गए। इस घटना के बाद, भारत ने पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में विद्रोह का समर्थन बंद करने तक द्विपक्षीय क्रिकेट न खेलने का निर्णय किया। वर्ष 2004 में, भारतीय टीम के पाकिस्तान दौरे के साथ क्रिकेट संबंध फिर से शुरू हुए, जब वाजपेयी जी एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने पाकिस्तान पहुँचे। इससे दोनों देशों के मध्य गतिरोध की स्थिति समाप्त हुई। वाजपेयी जी का यह दौरा बहुत सफल रहा, क्योंकि क्रिकेट प्रशंसक पाकिस्तानी आतिथ्य के अविश्वसनीय अनुभवों के साथ लौटे।

वर्ष 2005 में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्रिकेट कूटनीति के अंतर्गत पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को दिल्ली में एक एकदिवसीय मैच देखने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर कश्मीर, सियाचिन और सर क्रीक विवाद सहित विभिन्न मुद्दों पर भी वार्ता हुई। हालाँकि, वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद, दोनों देशों के राजनीतिक और क्रिकेट संबंध फिर से समाप्त कर दिए गए। वर्ष 2011 में कई उच्च-स्तरीय वार्ताओं के बाद, दोनों देशों ने अपने सभी लंबित मुद्दों, विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे, पर शांति वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की। तब से, दोनों देशों के संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं।

क्रिकेट कूटनीति केवल भारत-पाकिस्तान संबंधों तक ही सीमित नहीं है। वर्ष 2015 विश्व कप की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) देशों के नेताओं को क्रिकेट विश्व कप पर शुभकामनाएँ देने के लिए आमंत्रित किया था।

सामान्य तौर पर, क्रिकेट कूटनीति ने कई मुद्दों पर वार्ता फिर से शुरू करने और दोनों देशों की मनोदशा को समझने के लिए एक मंच प्रदान किया है। इसने कई बार दोनों देशों के मध्य तनाव को कम किया है और उन्हें क्रिकेट के खेल में एकजुट किया है। मेहमान टीम के प्रशंसकों और मेज़बान देश के खिलाड़ियों ने भी युद्ध के अलावा अन्य विषयों पर ध्यान देने के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार किया है। इससे दोनों देशों और उनके नागरिकों के बीच विश्वास बहाली में मदद मिली है।

अंतरिक्ष कूटनीति (Space Diplomacy)

अंतरिक्ष कूटनीति को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कूटनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को प्रभावित करने के साधन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपनी स्थापना के बाद से 39 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों और 4 बहुपक्षीय संगठनों के साथ अंतरिक्ष सहयोग संबंधी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है:

- **उपग्रह प्रणालियाँ और रॉकेट** (Satellite Systems and Rockets): इसरो CNES (फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी), नासा और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर विभिन्न मोर्चों पर कार्य कर रहा है, जिसमें उपग्रहों का विकास एवं भारत में एक तरल प्रणोदन उत्पादन संयंत्र (Liquid propulsion production plant) की स्थापना शामिल है। इसरो और CNES ने एक संयुक्त मिशन 'मेघा ट्रॉपिक्स' पर सहयोग किया और मिशन समझौता ज्ञापन को वर्ष 2020 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की थी। इसरो, नासा के साथ मिलकर NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) विकसित कर रहा है, जो पृथ्वी अवलोकन के लिए एक संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह है।
- **उपग्रह संचार** (Satellite Communications): 'पड़ोसी प्रथम' नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने छह पड़ोसी देशों के बीच संचार को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका को उपहारस्वरूप दक्षिण एशिया उपग्रह (South Asia Satellite - SAS) भेंट किया।
- **उपग्रह डेटा और आपदा प्रबंधन** (Satellite Data and Disaster Management): आपदा प्रबंधन में, इसरो COSPAS-SARSAT (COSPAS: Space System for the Search of Vessels in Distress, SARSAT: Search And Rescue Satellite-Aided Tracking) प्रणाली के माध्यम से आसियान देशों के साथ सहयोग कर रहा है। इस प्रणाली के तहत इसरो भारतीय उपग्रहों से प्राप्त डेटा को साझा करता है, जिससे खोज एवं बचाव कार्यों में मदद मिलती है।
- **उपग्रह नौवहन** (Satellite Navigation): IRNSS (NAVIC) की तैनाती के साथ, भारत पड़ोसी देशों को स्थलीय और समुद्री नौवहन, आपदा प्रबंधन, वाहन ट्रैकिंग, पैदल यात्रियों के लिए नौवहन सहायता तथा ड्राइवरों के लिए दृश्य और ध्वनि नौवहन आदि जैसी सेवाएँ प्रदान करता है।
- **क्षमता निर्माण** (Capacity Building): इसरो अन्य देशों की क्षमता निर्माण में भी संलग्न है, जो अपनी सुविधाओं तथा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में विशेषज्ञता को साझा करता है। इसरो भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान (IIRS) और देहरादून में स्थित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध केंद्र (CSSTE-AP) के माध्यम से अल्पकालिक और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम संचालित करता है।

वर्तमान में, इसरो का सहयोग JAXA (जापान), UAESA (UAE) और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों तक विस्तारित हो गया है। इन प्रयासों ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अग्रणी शक्ति के रूप में भारत की छवि को मज़बूत किया है। खोज एवं बचाव तथा आपदा प्रबंधन पर सहयोग ने भारत के लिए बहुत अधिक सद्भावना उत्पन्न की है, जिससे अंततः भारत की सॉफ्ट पावर को भी बढ़ावा मिलेगा।

आर्थिक कूटनीति (Economic Diplomacy)

आर्थिक कूटनीति का तात्पर्य सभी आर्थिक उपकरणों, जैसे- निर्यात, आयात, निवेश, ऋण, सहायता, मुक्त व्यापार समझौता आदि का उपयोग करके राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष विदेश नीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक संसाधनों को पुरस्कार या प्रतिबंध के रूप में उपयोग करना होता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से पूर्व, आर्थिक कूटनीति का मुख्य ध्यान विदेशी मुद्रा अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्रवाह सुनिश्चित करने पर था। उस अवधि के दौरान, विदेश और आर्थिक नीतियाँ अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यरत होने के कारण अधिक विभाजित थीं। इस अंतर को भरने के लिए, सस्ते तेल के आयात हेतु वार्ता भी एक उद्देश्य था। उसी समय, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) और संयुक्त राष्ट्र में समूह 77 के तहत विकासशील देशों के लिए विश्व अर्थव्यवस्था को अधिक अनुकूल बनाने का समर्थन किया।

वर्ष 1991 में शुरू किए गए सुधारों और भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल ही के प्रयासों ने भारत के विदेशी संबंधों को प्रभावित किया है। प्रमुख देशों के साथ उदार व्यापार व्यवस्था पर वार्ता, अन्य देशों के हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय निवेश, पड़ोसी देशों में परिवहन संबंधी अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करना, एक आर्थिक दानकर्ता के रूप में भारत की नई भूमिका और हमारी सीमाओं को पार करने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों जैसी मेगा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने से भारत की विदेश नीति में व्यापक परिवर्तन हुआ है।

व्यापार, क्षेत्रीय और उससे आगे बाज़ारों तक पहुँच, ऊर्जा सुरक्षा, और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की अनिवार्यताएँ, भारत के विदेशी संबंधों के लिए अभूतपूर्व संभावनाएँ लेकर आई हैं।

पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक जुड़ाव भारत की ऐक्ट ईस्ट नीति का आधार स्तंभ रहा है। आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) और बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN),

भारत-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्देश्य इस क्षेत्र के साथ आर्थिक एकीकरण को अधिक मज़बूत करना है। अपने पश्चिम में, अफ़गानिस्तान के साथ भारत पहले ही अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) पर हस्ताक्षर कर चुका है, तथा खाड़ी सहयोग परिषद् (GCC) के देश एक व्यापारिक ब्लॉक बनाने पर विचार कर रहे हैं और वे भारत के साथ सामान्य व्यापार उदारीकरण की दिशा में कार्य करने में रुचि रखते हैं। इसी प्रकार, अफ़्रीका के बढ़ते महत्त्व ने इस क्षेत्र में भारतीय निवेशकों को आकर्षित किया है। अफ़्रीका देश धातु खनिजों और ऊर्जा संसाधनों में समृद्ध है, जो भारत की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।

भारत ने बहुपक्षीय आर्थिक संगठनों के साथ व्यावहारिक जुड़ाव की नीति अपनाई है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत की आर्थिक कूटनीति के संदर्भ में, इसे विकासशील विश्व की ओर से असहमति की प्रमुख आवाज़ों में से एक के रूप में देखा जाता है। WTO में, सार्वजनिक भंडारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सब्सिडी पर भारत का रुख राष्ट्रीय हित को दर्शाता है। साथ ही, भारत ने दोहा दौर की वार्ताओं के समाधान से पहले किसी भी मुद्दे को शामिल किए जाने का विरोध किया है।

आर्थिक कूटनीति भारत को वैश्विक अवसरों का उपयोग घरेलू नागरिकों के लाभ के लिए करने का एक तरीका प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य गरीबी को कम करना और विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, भारत का आर्थिक प्रदर्शन एक सफल अंतर्राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है, जो एक राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति को महत्त्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित करने की इच्छा रखता है।

रक्षा कूटनीति (Defence Diplomacy)

रक्षा कूटनीति किसी भी ऐसी सैन्य गतिविधि को संदर्भित करती है, जिसका एक स्पष्ट कूटनीतिक उद्देश्य होता है; अर्थात्, ऐसी गतिविधियाँ, जिनका प्राथमिक उद्देश्य दूसरे देशों में भारत के प्रति सद्भावना को बढ़ावा देना हो। रक्षा कूटनीति में अनेक प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनमें कुछ निम्न प्रकार हैं:

- रक्षा मंत्रालय (MOD) के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षा कार्यक्रम, जिनमें विदेशी छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में अध्ययन के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- सैन्यकर्मियों, अल्पकालिक प्रशिक्षण दलों, और नागरिक व सैन्य सलाहकारों को दीर्घावधि तक विदेशी सरकारों के साथ काम करने के लिए भेजने का प्रावधान।
- जहाज़ों, विमानों और अन्य सैन्य इकाइयों के दौरे;
- सभी स्तरों पर मंत्रियों, सैन्य और नागरिक कार्मिकों द्वारा आंतरिक एवं बाह्य यात्राएँ;
- आपसी समझ को बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों के मध्य वार्ताएँ, सम्मेलन और संगोष्ठियाँ;
- सैन्य अभ्यास आदि

स्वतंत्रता के बाद से भारत ने ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली अपनी बड़ी, पेशेवर सैन्य शक्ति का लाभ उठाते हुए अपने बाह्य संबंधों में रक्षा कूटनीति का उपयोग किया है। अपने आकार और उत्तर-औपनिवेशिक विश्व में एक मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत "एक प्रमुख राज्य" है, जिसकी भूमिका "एशिया में दीर्घकालिक शांति, स्थिर शक्ति संतुलन, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है।" "कोई क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा नहीं और लोकतंत्र सहित किसी विचारधारा का कोई निर्यात नहीं" भारत की विदेश नीति और रक्षा कूटनीति के मूल सिद्धांत रहे हैं।

रक्षा कूटनीति के प्रारंभिक प्रयास, इसके औपनिवेशिक विरासत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM), साम्राज्यवाद-विरोधी व उपनिवेशवाद-विरोधी आंदोलनों (नाइजीरिया, ईरान, इराक़, नामीबिया, दक्षिण अफ़्रीका के रंगभेद विरोधी प्रयास, आदि) के समर्थन का एक संयोजन थे। पर्वतीय युद्ध, उग्रवाद/आतंकवाद विरोधी अभियानों और इसकी प्रभावशाली सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली में भारत के विशाल अनुभव का उपयोग प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास के माध्यम से जीवंत द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए किया गया है।

भारत की समुद्री डकैती और अन्य उपद्रवी गतिविधियों को नियंत्रित करने की क्षमता ने निश्चित रूप से भारत को एक शांतिपूर्ण सीमा बनाए रखने और अपने सामर्थ्य को एक सूक्ष्म और विवेकपूर्ण तरीके से प्रदर्शित करने की अनुमति दी है, जो क्षेत्र के छोटे तटीय देशों की समुद्री आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप है।

रूस, इज़रायल, फ़्रांस, अमेरिका और अन्य देशों के साथ रक्षा साझेदारी इन देशों के साथ रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भारत द्वारा स्थापित की गई रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाती है। 21वीं सदी में नए अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बन रहे हैं और कोई भी राष्ट्र यदि अपने सुरक्षा वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए अपने सभी साधनों और संसाधनों का उपयोग नहीं करता है, तो वह अस्तित्व और विकास के लिए संघर्षरत रहेगा। वहीं, जो राष्ट्र सैन्य कूटनीति के लिए एक ठोस दृष्टिकोण विकसित करते हैं और उसे अपनाते हैं, यद्यपि वे पूर्णत: सुरक्षित नहीं, किंतु सौम्य सुरक्षा वातावरण का लाभ उठा सकते हैं।

भारत की समकालीन सुरक्षा चुनौतियाँ (India's Contemporary Security Challenges)

शीत युद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौलिक पुनर्गठन की आवश्यकता उत्पन्न की और एक बेहतर सुरक्षा वातावरण विकसित करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण अवसर प्रदान किया। शीत युद्ध के पश्चात्, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण से उत्पन्न अनेक प्रकार के दबावों ने भारत के समक्ष जटिल और बहुस्तरीय चुनौतियाँ तथा अवसर उत्पन्न किए हैं। बदली हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत को नई चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाकर, उनका सामना करना होगा तथा अपने रणनीतिक एवं राजनीतिक विकल्पों को अधिकतम करना

होगा, जिसमें मुख्य रूप से उसे अपनी शक्ति क्षमता और सौदेबाज़ी की लाभदायक स्थितियों का उपयोग करना होगा।

भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे देशों से उत्पन्न सुरक्षा ख़तरों से घिरा हुआ है। भू-रणनीतिक परिकल्पनाओं से परे, भारत ने हाल ही के समय में अमेरिका के साथ सहयोग से लाभ उठाया है, जबकि वह चीन और पाकिस्तान से लगातार संभावित सुरक्षा ख़तरों का सामना कर रहा है। भारत की क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चिंताएँ इसकी सैन्य आधुनिकीकरण, समुद्री सुरक्षा और परमाणु नीतियों में परिलक्षित होती हैं। फिर भी, घरेलू सुरक्षा चिंताएँ भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण को प्रभावित करती रहती हैं। कुछ सुरक्षा चुनौतियों में शामिल हैं:

- **सीमा पार आतंकवाद** (Cross-Border Terrorism): अधिकांश बाह्य ख़तरे चीन के साथ अनसुलझे सीमा विवाद और जम्मू-कश्मीर में जारी सीमा पार जिहादी आतंकवाद से उत्पन्न होते हैं, जो पाकिस्तान की आईएसआई (ISI) और पाकिस्तान-स्थित इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद द्वारा प्रायोजित होते हैं। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय जिहादी समूहों जैसे तालिबान और अल-कायदा के साथ जटिल रूप से अंतर्संबंधित हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद** (International Terrorism): भारत 1970 के दशक के अंत से अब तक सबसे भीषण और लगातार आतंकी घटनाओं का सामना कर रहा है, पहले पंजाब में, फिर जम्मू-कश्मीर में, और हाल ही के वर्षों में देश के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार की घटनाएँ होती रही हैं। वर्ष 1993 के बॉम्बे धमाके इस क्रमिक आतंकवाद का प्रथम उदाहरण था। भारत के पूजा स्थल, तीव्र आर्थिक संवृद्धि के प्रतीक, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान, लोकप्रिय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं भारत के जीवंत लोकतंत्र के प्रतीक आदि सभी को व्यवस्थित रूप से आतंकवादी हमलों का निशाना बनाया गया है। जहाँ विश्व के अधिकांश भागों में गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा घटित आतंकवादी घटनाएँ देखने को मिलती हैं, वहीं भारत में यह शत्रुतापूर्ण पड़ोस की राज्य एजेंसियों द्वारा प्रायोजित और समर्थित होता है।
- **इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक़ एंड सीरिया** (ISIS): ISIS, जिसे कभी-कभी अल-तौहीद या इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक़ एंड द लेवेंट (ISIL) भी कहा जाता है, एक सुन्नी आतंकवादी जिहादी संगठन है, जो मुख्य रूप से इराक और सीरिया में सक्रिय है। हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों से लोगों के गिरफ़्तार होने की घटनाएँ इस समूह से होने वाले संभावित ख़तरों को स्पष्ट करती हैं। हालाँकि, भारतीय इस्लाम की समन्वयात्मक प्रकृति को देखते हुए, इस समूह के लिए मुसलमानों के बीच लोकप्रिय होना अत्यंत कठिन है, किंतु ISIS के विश्व दृष्टिकोण और रणनीति से प्रेरित व्यक्तिगत (Lone-wolf) हमले सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। इसके प्रभाव को रोकने के लिए भारत को उच्च स्तरीय खुफ़िया और आतंकवाद विरोधी अभियानों को जारी रखना आवश्यक है। इसके साथ ही, कट्टरपंथ का सामना करने और पश्चिमी सरकारों की तरह विशिष्ट डी-रेडिकलाइज़ेशन कार्यक्रम लागू करने के लिए राज्य और मुस्लिम धार्मिक नेताओं के बीच बेहतर समन्वय भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है।
- **समुद्री सुरक्षा** (Maritime Security): रणनीतिक और आर्थिक केंद्र बिंदु बदल रहे हैं, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र, लगभग प्रत्येक प्रमुख शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है। हिंद महासागर भारत के निकटतम और विस्तारित समुद्री पड़ोसी देशों के साथ एक रणनीतिक पुल के रूप में कार्य करता है। भारत के राष्ट्रीय और आर्थिक हित हिंद महासागर के साथ अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। समुद्री क्षेत्र में भारत के समक्ष विद्यमान महत्त्वपूर्ण चुनौतियों में गैर-राज्य अभिकर्ता भी एक प्रमुख चुनौती है, जैसे कि वर्ष 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम देने वाले; समुद्री डकैती, तटीय देशों में चीन की उपस्थिति, नौवहन की स्वतंत्रता तथा अन्य।
- **साइबर सुरक्षा** (Cyber Security): साइबरस्पेस मुख्य रूप से नागरिक उपयोग के लिए तैयार किया गया था। हालाँकि, अब यह युद्ध के एक नए क्षेत्र के रूप में उभरा है। डिजिटल पहुँच के बढ़ने तथा नक़दी रहित लेन-देन के लिए बढ़ते दबाव के कारण भविष्य में भारत में साइबर हमलों की संभावना बढ़ जाएगी। महत्त्वपूर्ण अवसंरचनात्मक ढाँचों (बैंक, अस्पताल, परमाणु संयंत्र आदि) पर साइबर हमले (मैलवेयर, रैनसमवेयर आदि) राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा ढाँचे को भी बड़े स्तर पर क्षति पहुँचाने की क्षमता रखते हैं।
- **मादक पदार्थों की तस्करी** (Drug Trafficking): हेरोइन और चरस के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्रों स्वर्ण त्रिभुज (Golden Triangle) और स्वर्ण अर्धचंद्र (Golden Triangle) (अफ़गानिस्तान-पाकिस्तान-ईरान) से निकटता ने भारत की सीमा को मादक पदार्थों की तस्करी के प्रति संवेदनशील बनाया है। भारत मादक पदार्थों की तस्करी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप, विशेष रूप से युवाओं में नशीली दवाओं का दुरुपयोग सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है।
- **परमाणु ख़तरा** (Nuclear Threat): भारत ने परमाणु हथियारों के प्रथम प्रयोग न करने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ, पाकिस्तान के व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए अन्य प्रकार की शक्ति या दबाव के विकल्प के रूप में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया है। फिर भी, पाकिस्तान द्वारा परमाणु क्षमताओं में तेज़ी से सुधार और चीन द्वारा क्रमिक परमाणु आधुनिकीकरण ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिवेश को इस तरह से बदल दिया है कि निरोधक चुनौतियाँ और भी बढ़ गई हैं।